

कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगा झटका ज्ञानवापी तहखाने की छत पर होती रहेगी नमाज, मरम्मत पर भी रोक



वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी केस में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने वालों को रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब कि नमाज के लिए मुस्लिम इकट्ठा होते रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने तहखाने में मरम्मत कराने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया है। सिविल जज सीनियर डिबीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में तहखाने में चल रही पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के

कस्टोडियन डीएम वाराणसी को किसी भी प्रकार की मरम्मत का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी। और यथास्थिति को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि जब जनवरी में कोर्ट व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिलने के बाद एक संस्था की तरफ से एक याचिका दायी थी। इस याचिका में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई थी।

पन्ना का मजदूर बना करोड़पति, मिला मध्यप्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा हीरा

पन्ना। बुंदेलखंड के पन्ना की रत्नगर्भ धरती ने एक बार फिर से हीरा उगला है और मजदूर को रातों-रात करोड़पति बना दिया है। यहां एक गरीब मजदूर को पन्ना की धरती से हीरा मिला है, जिससे अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नजारा पन्ना के हीरा कार्यालय का है, जहां एक मजदूर 32 कैरेट 80 सेंट का उज्जवल नायाब किरम का हीरा लेकर आया और हीरा कार्यालय में जमा कराया है। दरअसल, मजदूर स्वामीदीन अपने सरकोहा ग्राम के खेत में हीरा की खदान लगाए हुए था, जहां उसे यह हीरा मिला है। मजदूर स्वामीदीन हीरा पाकर बहुत खुश है। क्योंकि वह रातों-रात करोड़पति जो बन गया है। जानकारी के मुताबिक, तीन महीने पूर्व यह खदान सरकोहा ग्राम में लगाई गई थी और इस खदान में तीन पार्टनर थे तो अब यह हीरा भी तीन पार्टनरों का है। इस हीरे से मिलने वाली रकम तीन हिस्सों में बांटी जाएगी। बता दें कि हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा हो गया है, जिसे आगामी समय में नीलामी में रखा जाएगा और इसे ऑक्शन में बेचा जाएगा। हीरे की नीलामी बिक्री से मिलने वाली रकम की 12 प्रतिशत की रॉयल्टी काटकर शेष राशि हीरा पाने वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी। वहीं, इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है।

गलवां घाटी और पूर्वी लद्दाख समेत चार क्षेत्रों से पीछे हटे चीन और भारत के सैनिक

नई दिल्ली। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात रंग लाई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने की सहमति बनी। इसके बाद गलवां घाटी और पूर्वी लद्दाख समेत चार क्षेत्रों से सैनिक पीछे हट गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ङिंग ने कहा कि दोनों सेनाएं चार क्षेत्रों में पीछे हट गई हैं। सीमा पर स्थिति स्थिर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन-भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के मौलिक और दीर्घकालिक हितों

में है। यह क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भी जरूरी है। रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के प्रमुख सहमति को लागू करने, आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने, निरंतर संचार बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थितियां बनाने पर सहमत हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में वांग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत को दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। एक-दूसरे के बीच एकता और सहयोग अपनाकर उपभोग से बचना चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पक्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने मतभेदों को ठीक से संभालेंगे।

‘सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, यहां हिन्दी में दलीलें नहीं दे सकते’

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता द्वारा हिन्दी में दलीलें पेश करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा दायर एक याचिका में बस्ती जिले से प्रयागराज में रकूरता और दहेज के मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें हिन्दी में पेश कीं। याचिकाकर्ता ने जब अदालत के समक्ष अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है। न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, इस न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। आपने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखी, इसलिए हमने आपको

बीच में नहीं रोका ताकि आप अपनी बात पूरी तरह से कह सकें। यहां दो न्यायाधीश बैठे हैं। आपको बिना यह सुनिश्चित किए कि न्यायालय आपको समझ पा रहा है या नहीं, हिंदी में इस तरह दलीलें पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की कि वह अपनी दलीलें अंग्रेजी में पेश करेंगे, और कार्यवाही फिर से शुरू हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। **यह कहता है संविधान का अनुच्छेद 348** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए, जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। यह प्रावधान उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। हालांकि, यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत, कानूनों और फैसलों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए।



2022 में भी हुआ था ऐसा ही मामला यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने भाषा की बाधा का सामना किया हो। 2022 में भी, जब एक याचिकाकर्ता ने हिन्दी में दलीलें पेश करने की कोशिश की थी, तब न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने उन्हें याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। उस मामले में, याचिकाकर्ता की सहायता के लिए

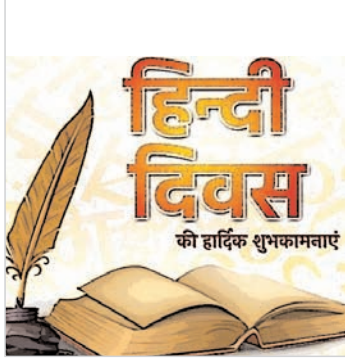
एक वकील नियुक्त किया गया था ताकि वह उचित भाषा में अपनी दलीलें पेश कर सके। **सीजेआई कर चुके हैं क्षेत्रीय भाषाओं की वकालत** हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक शिक्षा और कार्यवाही को क्षेत्रीय भाषाओं में करने की वकालत की थी ताकि न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने वकीलों के अपने

आरामदायक भाषा में केस प्रस्तुत करने की संभावना पर जोर दिया था और सुझाव दिया था कि स्थानीय भाषाएं देश में न्याय वितरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने की योजना शुरू की थी। **एक माह पहले यह बोले थे चीफ जस्टिस** देश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक माह पहले 11 अगस्त को कहा कि लोकतंत्र को वास्तव में फलने-फूलने के लिए सभी नागरिकों को राष्ट्र की संस्थाओं से वास्तव में जुड़ाव महसूस करना चाहिए। न्यायपालिका से लोगों के जुड़ाव में भाषा सबसे बड़ी बाधा है। देश के हाईकोर्ट ज्यादातर काम अंग्रेजी में करते हैं और भाषाई विविधता वाले देश में यह एक बड़ी चुनौती है। सीजेआई ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस चुनौती से निपटने में बड़ी भूमिका निभाता है। सीजेआई चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी की ओर से देश की अदालतों में प्रौद्योगिकी के परिदृश्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

मिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत में चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, शनिवार 14 सितम्बर 2024



दिल्ली शराब घोटाला- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में भी मिली जमानत, जेल से हुए रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर कसा तंज

11 साल बाद भी सीबीआई ‘पिंजरे में बंद तोता’!

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके लिए उन्हें 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो अपील दायर की थी जिसमें जमानत की अपील के साथ-साथ सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी सही थी या नहीं, इस पर दोनों जजों की राय अलग थी। एक तरफ जहां जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया तो वहीं जस्टिस भुइयां ने इस पर सवाल उठाया है। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की टाईमिंग पर सवाल खड़े करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि यह गिरफ्तारी केवल इसलिए हुई ताकी ईडी के मामले मिली जमानत को विफल किया जा सके। जस्टिस भुइयां ने आगे कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं। सीबीआई को अपनी ‘तोता छवि’ से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनिवार्य तरीके से न हो। किसी देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वह एक पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह शक से ऊपर उठना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। इन शर्तों के मुताबिक न तो वे सचिवालय जा सकेंगे और न ही किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई थी, वही शर्तें सीबीआई केस में लागू की गई हैं। शुक्रवार को बेल मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा भी हो गए हैं।



अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों पर मिली जमानत

- अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे।
- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक एलजी की ऐसा करना जरूरी न हो।
- अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
- किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।
- इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

22 महीने बाद अवानक एक्टिव हुई सीबीआई

जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने मार्च 2023 में केजरीवाल से पूछताछ की गई थी लेकिन तब उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सीबीआई ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। सीबीआई को 22 महीनों तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन फिर अवानक एक्टिव हो गई और हिरासत की मांग की। सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई ने इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए की थी।

11 साल पहले यह था ‘पिंजरे में बंद तोता’ विवाद

आज से करीब 11 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ‘पिंजरे में बंद तोता’ कहा था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोर्ट की उस टिप्पणी से सिपायी भूवाल आ गया था। मामला कोयला आबंटन घोटाले से जुड़ा था। 9 मई, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस घाटले की जांच में सरकार की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की थी। उसी सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई उसी भाषा में बात कर रही है, जो उसे उसके मालिक ने पढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह तोता विवाद यहीं तक खत्म नहीं हुआ था। तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के बयान ने इस विवाद को और भी हवा दे दी थी। रंजीत सिन्हा ने मीडिया में बयान दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सही है, कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं कहा। यानी सीबीआई सरकार के बंद पिंजरे का तोता है। रंजीत सिन्हा के इस बयान के बाद सियासत और भी गरमा गई थी। बीजेपी तब विपक्ष में थी। पार्टी नेताओं ने यूपीए सरकार खासतौर पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमला तेज कर दिया था। इस केस की सुनवाई में जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसफ शामिल थे।

सिसोदिया को देख लिपट गए केजरीवाल

156 दिन की जेल काटने के बाद अब केजरीवाल रिहा हो गए हैं। वे जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पहुंचे। वहां अपने दायी हाथ कहे जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को देखते ही उनसे लिपट गए। दोनों के बीच 18 महीने बाद मुलाकात हुई थी। देर शाम जेल से निकलने के बाद केजरीवाल ने वहां मौजूद आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। इसके बाद उनके घर तक रोड शो हुआ। जब केजरीवाल घर पहुंचे तो उनकी मां ने उन्हें तिलक लगाया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

गुलामी का एक और निशान मिटा...

पोर्ट ब्लेयर अब कहलाएगा श्री विजय पुरम, केंद्र ने बदला नाम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में पोर्ट ब्लेयर के नए नाम का ऐलान किया गया। अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत देश को औपनिवेशिक पहचान से मुक्त करने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजय पुरम करने का निर्णय लिया है। अब गुलामी का एक और निशान मिटा दिया गया है। उन्होंने लिखा कि पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। विजय पुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक



और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। यह वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया था और वह सेल्युलर जेल भी है जहां वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। बता दें कि पिछली जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर इस केंद्र शासित प्रदेश के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा था। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी वहां अनावरण किया था, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया गया है। इस द्वीप को पहले रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था।

मध्यप्रदेश में सामान्य से 5.8 इंच ज्यादा बारिश

भोपाल। मध्यप्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। सीजन की सामान्य बारिश का कोटा सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही पूरा हो चुका है। पिछले तीन दिन से जो सिस्टम एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से अब तक 40.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 34.4 इंच से 5.8 इंच ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 सितंबर तक इसी तरह बारिश का दौर जारी रहेगा। अभी मानसून की विदाई में 18 दिन बाकी हैं लेकिन एमपी के तालाब 65 फीसदी और बांध भी 90 फीसदी तक भर चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 10–15 दिन का एक और सिस्टम एक्टिव होने के आसार हैं। पिछले पांच साल के आंकड़े देखें तो इस बार बारिश ने साल 2022 को छोड़कर 2020, 2021 और 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2022 में सबसे ज्यादा 46 इंच बारिश हुई थी। वहीं, साल 2023 में औसत से 0.1 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी।

रेप केस में फंसे विंग कमांडर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दी है जिन पर एक महिला फ्लाईंग ऑफिसर ने रेप का इल्जाम लगाया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने पिछले दो साल से हो रहे यौन शोषण उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की बात कही थी। एक रिपोर्ट की माने तो हाई कोर्ट के

ऑर्डर में कहा गया है कि विंग कमांडर की गिरफ्तारी से उनके करियर और इज्जत को नुकसान पहुंच सकती है। अदालत ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से पहले उसकी इजाजत लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच जारी रखने की बात तो कही है लेकिन विंग कमांडर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगर विंग कमांडर को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत

दी जाएगी। महिला फ्लाईंग ऑफिसर ने अपने बयान में बताया कि 31 दिसंबर 2023 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें कमरे में बुलाया और वहां उनके साथ जबरदस्ती की। उन्होंने दावा किया कि विंग कमांडर ने उन्हें ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अधिकारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। महिला अधिकारी का आरोप

है कि शिकायत करने पर अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की और सही ढंग से जांच नहीं की। महिला अधिकारी ने आगे कहा कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उनके पर्सनल चैट की निगरानी की जा रही है और उनके साथ संपर्क करने वाले लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है।

जामगेट पर सैन्य अफसरों से लूट के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर के पास स्थित जामगेट पर हाल ही में एक गंभीर अपराध की घटना सामने आई है। इसमें दो आर्मी अफसरों के साथ लूटपाट, मारपीट और एक महिला मित्र से कथित गैंगरेप शामिल है। इस मामले में सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगरेप पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीड़िता के बयान नहीं हुए हैं और मेडिकल में भी गैंगरेप पर साफ जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की और कई थानों की टीमों को आरोपी गिरफ्तार करने के लिए तैनात किया। इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया आरोपियों की तलाश में 10 थानों की टीमें लगाई गई थीं। शुक्रवार को फरार आरोपी रोहित पिता ज्ञान सिंह गिरवाल निवासी नंदगांव, संदीप पिता दिनेश सिंह वारिया निवासी चैनपुर और सचिन पिता राधेश्याम मकवाना पकड़े गए हैं। इनके पहले गुरुवार को अनिल पिता मदन बारोर, पवन पिता लाल बंसुनिया और रितेश पिता देवेश भाभर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया जा चुका है।

अनिल था मास्टरमाइंड

जांच के दौरान पता चला कि इस अपराध का मास्टरमाइंड अनिल था। अनिल एक शराब की दुकान पर काम करता था और मानपुर क्षेत्र में मुखबिरी करता था। 10 सितंबर की रात, जब अनिल जामगेट से गुजर रहा था, उसने म्यूजिक सुनकर वहां रुकने का निर्णय लिया। उसने देखा कि आर्मी अफसर और उनकी महिला मित्र कार में



थे। अनिल ने इस मौके को भांपते हुए अपने साथियों को फोन कर बुलाया और कहा कि मामला अच्छा फंसा है, बढ़िया दांव हो जाएगा। इस सूचना के आधार पर आरोपियों ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया।

अनिल ने ही कट्टा दिखाकर धमकाया

अनिल ने खुद कट्टे का उपयोग करके आर्मी अफसरों को धमकाया और उनके साथ लूटपाट की। इस दौरान एक महिला मित्र से कथित गैंगरेप की घटना भी सामने आई। घटना के मास्टरमाइंड के तौर पर अनिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी आरोपियों तक पहुंची।

पुराने थाने पहुंची थी ट्रेनी आर्मी अफसर की टोली लूटे गए रुपए आपस में बांट लिए थे गिरफ्तार आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली है। आरोपियों ने आर्मी के अफसरों और महिला मित्रों से लूटे गए रुपए आपस में बांट लिए थे। सोने की चेन छिपा दी थी। पुलिस अब लूटा गया सामान जब्त करने की कोशिश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सेना के अफसर भी थाने पहुंचे। एहतियात के तौर पर आरोपियों को बड़गाँदा थाने पर नहीं रखा गया है। बता दें कि घटना से आर्मी की एक टोली नाराज है। इसके चलते गुरुवार रात को वह बड़गाँदा के पुराने थाने तक पहुंच गई थी लेकिन यहां उन्हें कोई नहीं मिला। बाद में सैन्य

पुलिस के आने की सूचना देख सभी ट्रेनी आर्मी अफसर यहां से तुरंत वापस अपनी यूनिट में लौट गए थे।

अनिल और रितेश के मन में आया लालच

आरोपियों ने सैन्य अफसरों और उनकी महिला मित्रों को घेर लिया। रितेश के पास पिस्टल थी। इसे देखकर सैन्य अफसरों ने कहा कि जो चाहे ले लो, लेकिन कोई हरकत मत करना। अनिल और रितेश के मन में लालच आ गया, उन्हें लगा कि बड़ा काम हो सकता है। इस पर उन्होंने दस लाख रुपए की डिमांड कर दी।

जंगल में म्यूजिक की आवाज सुनकर पहुंचे थे बदमाश

जानकारी के अनुसार, सैन्य अफसर तेज आवाज में जंगल में म्यूजिक सुन रहे थे। जिसकी आवाज सुनकर बदमाश मौके पर पहुंचे थे। वहीं, सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूद एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दिन बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में युवती के शरीर पर चोट के निशान तो पाए गए हैं, लेकिन दुष्कर्म को लेकर डॉक्टरों कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। युवती ने भी इसे बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ग्रामीण एसपी हितिका वासल के अनुसार आर्मी के अधिकारियों के बयान के आधार पर लूट, मारपीट, फिरौती और सामूहिक दुष्कर्म की आशंका में केस दर्ज किया गया। युवती के बयान के बाद केस में धाराएं अपडेट की जाएंगी। इस

मामले में राजनीति भी गरमा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पर क्यों चुप हैं। हम मग्न में हुई घटना पर अपराधियों को सख्त सजा दिलवाएंगे।

पटवारी बोले-महू रेपकांड में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार शामिल

एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस रेप कांड में बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों के संलिप्त होने का आरोप लगाया है। भोपाल में जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा- मग्न में फिर एक बार साबित हुआ कि जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है उसमें भाजपा के कार्यकर्ता और उनके रिश्तेदार सामने आते हैं। महू की घटना के पीछे भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के नाम आए हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह भामर दूसरे भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम इस घटना में सामने आए हैं यह क्या मैसेज है?

बीडी बोले-कुर्सी बचाने झूठ बोल रहे पटवारी पटवारी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सरकार को आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की सरकार में आरोपी बच नहीं सकते। बीजेपी सरकार में कानून, कानून की तरह ही काम करता है। जिन्हें झूठ बोलना है उनका क्या कर सकते हैं।

लसूड़िया में गोदाम में लगी भीषण

आग धमाकों से फैली दहशत

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर के लसूड़िया में एसआर कंपाउंड हिमालय बस बॉडी बिल्डिंग के गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कई धमाके भी सुनाई दिए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा था। गोदाम में बसों के लिए रॉ मटेरियल और डीजल टैंक रखे हुए थे, जिससे आग और फैल गई। गोदाम मालिक मनीष यादव ने बताया कि वह खाना खाने गए थे, इस दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी थर्माकोल की शीट पर गिरी, जिससे आग लग गई और वहां रखे अन्य रॉ मटेरियल में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अफसरों के अनुसार, यहां पर बसों की बॉडी बनाने का काम होता है। हादसे के समय कुछ गाड़ियां भी अंदर थीं, जो आग से जल कर खाक हो गईं। आग इतनी भीषण थी कि दमकलकर्मियों को लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफलता मिली। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, अधिकारी आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रहे हैं।

थर्माकोल की शीट पर गिरी चिंगारी

मौके पर मौजूद गोदाम मालिक मनीष यादव ने बताया कि वह खाना खाने गए थे, इस दौरान



शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी थर्माकोल की शीट पर गिरी, जिससे आग लग गई और वहां रखे अन्य रॉ मटेरियल में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अफसरों के मुताबिक यहां पर बसों की बॉडी बनाने का काम होता है। हादसे के समय कुछ गाड़ियां भी अंदर थीं। आग से वह भी जल कर खाक हो गई। फिलहाल आग पूरी तरह से काबू में है।

आग से हुए नुकसान का आकलन

आग से हुए नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन अनुमानित तौर पर करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम में रखे रॉ

मटेरियल और गाड़ियां पूरी तरह से जल कर खाक हो गईं।

अनदेखी पड़ रही भारी

आग की घटना से यह साबित होता है कि अग्नि सुरक्षा के उपायों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गोदामों और फैक्ट्रियों में अग्नि सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही, नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

कारखाने की जमीन पर बने

मकान नगर निगम ने तोड़े

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। नगर निगम ने शुक्रवार को तीन स्थान पर मकान तोड़े। पालदा क्षेत्र में कारखाने के लिए आवंटित जमीन पर मकान बना लिए थे। जिसमें पांच परिवार भी रह रहे थे। इसके अलावा गाड़ियों की धुलाई के लिए एक सर्विस सेंटर भी बना रखा था। जिसे नगर निगम के अमले ने तोड़ दिया। सुबह मौके पर पहुंचे अफसरों ने पहले परिवारों को मकान खाली करने के लिए कहा। परिवार के लोग पहले आनाकानी कर रहे थे, लेकिन अफसरों की सख्ती के बाद उन्होंने गृहस्थी का सामान बटोरना शुरू कर दिया। इसके बाद अवैध हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। सामान निकालने के दौरान एक युवक को चोट भी लग गई। मकान जब तोड़े जा रहे थे तब परिवार की दो महिलाएं काफी हंगामा कर रही थी। बाद में दोनों रौने लगीं। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अभियान



प्रभावित नहीं हुआ। दो घंटे में अवैध निर्माण जमींदोज हो गया। अफसरों ने कहा कि पालदा क्षेत्र में प्लॉट उद्योगों के लिए आवंटित है, लेकिन बगैर अनुमति के आवासीय उपयोग किया जा रहा था और किराया भी वसूला जा रहा था।

अवैध मकान तोड़ने के लिए कुछ दिनों पहले नोटिस दिया गया था। नगर निगम ने खजूरी बाजार और नृसिंह बाजार से

खतरनाक मकान भी तोड़े। 60-70 साल पुराने यह मकान झांकी मार्ग पर है। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों से पहले खतरनाक मकान तोड़ता है। अभी तक पांच खतरनाक मकान तोड़े जा चुके हैं। इंदौर में 100 से ज्यादा खतरनाक मकान हैं, लेकिन कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण ज्यादातर मकान तोड़े नहीं जाते हैं।

चाचा नेहरू अस्पताल से काटे चंदन

के तीन पेड़, गार्ड को अड़ाई बंदूक

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल से तीन चंदन के पेड़ काट कर आठ बदमाश ले गए। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो बदमाशों ने बंदूक अड़ाकर उसे धमकाया और इत्मीनान से पेड़ काट कर ले गए। चंदन चोरों ने एक पेड़ को नीचे से काटा। फिर उसके तने के उपरी हिस्से को

काटा। परिसर में 15-20 साल पहले यह पेड़ लगाए गए थे गार्ड ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात को बदमाश परिसर में आए। उनकी संख्या आठ थी। पहले परिसर में चार बदमाश दाखिल हुए। उन्होंने एक पेड़ काटना शुरू किया। गार्ड को आहत हुई तो वह परिसर में वहां पहुंचा, जहां पेड़ काटे जा रहे थे। इस बीच उसे

बंदूक अड़ाकर तीन बदमाशों ने काबू कर लिया। इसके बाद परिसर में लगे दूसरे पेड़ों के तने काटने लगे। परिसर के चार पेड़ काटने में उन्हें आधे घंटे का समय लगा। इसके बाद वे भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिसर में लगे कैमरे भी खंगाल रही है, ताकि बदमाशों को सुराग मिल सके।

बाइक सवारों ने युवती को किया बेड टच

लोगो ने पीटा, केस दर्ज

इंदौर। एमआईजी में बाइक सवारों ने एक युवती को बेड टच किया। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दोनों लड़कों को पकड़ लिया। बाद में युवती ने लोगों के साथ मिलकर उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एमआईजी पुलिस ने बताया

कि 23 साल की युवती को शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। वह कॉल सेंटर में काम करती है और विजय नगर में अपनी मौसी के घर बजरंग नगर जा रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवारों ने उसे बेड टच किया। युवती चिल्लाई तो भीड़ ने उसे

पकड़ लिया। और थाने जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवती ने मौसी और मौसा के साथ एमआईजी थाने जाकर आरोपी शादाब खान, निवासी खजराना और सौरव दुबे निवासी नंदा नगर पर छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज करा दिया।

जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, बेसमेंट में संचालित सर्विस सेंटर, दुकानें सील

इंदौर। बेसमेंट में कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार से सख्त रुख अपनाया है। इस कड़ी में एमजी रोड स्थित दो सर्विस सेंटरों और पलासिया स्थित नवनीत प्लाजा की कुछ दुकानों को सील किया गया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। टीम ने एमजी रोड और

ग्रेटर कैलाश रोड स्थित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। इसमें एमजी रोड स्थित खंडेलवाल सुजुकी और कासलीवाल होंडा का सर्विस सेंटर बेसमेंट में संचालित होना पाया गया। इन्हें मौके पर सील किया गया। इसी प्रकार ग्रेटर कैलाश रोड स्थित नवनीत प्लाजा में पार्किंग के स्थान पर दुकानें संचालित होना पाई गई जिन्हें सील किया गया।

वार्ड 83 के उपचुनाव में जीती भाजपा, कांग्रेस प्रत्याशी 4 हजार वोट से हारे

सिटी चीफ इंदौर

इंदौर। इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 के उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई है। भाजपा के जीतू राठौर को 6490 और कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2235 वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार 4255 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि मतगणना के लिए 15 टीमें बनाई थी। 11 टेबलों पर गणना हुई और 4 टीमें रिजर्व में थीं। शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में मतगणना सुबह 9 बजे शुरू हुई। पार्षद कमल लड्डा के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए हैं। बुधवार को वोटिंग हुई थी। भाजपा से जीतू राठौर, कांग्रेस विकास जोशी सहित 6 उम्मीदवारों मैदान में थे। इस उप चुनाव में खास बात यह रही की भाजपा का गढ़



कहे जाने वाले इस वार्ड में मतदाताओं ने चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। इस वार्ड में 11 सितंबर को 41.32

प्रतिशत ही मतदान हुआ। जो पिछली बार से कम है। 21 हजार 700 मतदाताओं में से महज 8900 वोटर्स ने ही वोट डाले।

कमल लड्डा 8 हजार वोट से जीते थे

इंदौर नगर निगम चुनाव में कमल लड्डा की जीत सबसे बड़ी जीत थी। बता दें कि इस वार्ड में अब लड्डा के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ है। 2022 में हुए चुनाव में इस वार्ड से बीजेपी के कमल लड्डा की जीत 8803 वोट से हुई थी। कमल लड्डा को उस समय 11 हजार 280 वोट मिले थे। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के आशीष लाहोटी को 2 हजार 477 वोट मिले थे। वहीं वार्ड 83 के बाद सबसे बड़ी जीत वार्ड 81 में बीजेपी के अभिषेक बबलू शर्मा की हुई थी। शर्मा 8 हजार 696 वोट से जीते थे।

भोपाल एयरपोर्ट पर मौसम की खराबी से प्रभावित नहीं होगी लैंडिंग

सिटी चीफ भोपाल ।
भोपाल। मौसम की खराबी की वजह से होने वाली विमानों की लैंडिंग में परेशानी से भोपाल एयरपोर्ट के यात्रियों को निजात मिलने वाली है। यहां सुविधा सुधार के लिए किए जा रहे कामों को अब आकार मिल चुका है। जल्दी ही लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। राजधानी भोपाल का राजाभोज एयरपोर्ट अब यात्री सुविधाओं के तौर पर नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। यहां जुटाई जा रही सुविधाओं के चलते लैंडिंग करने वाली फ्लाइटों पर अब मौसम की खराबी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक पसरे हालत में मौसम खराबी के कारण कई फ्लाइटों की लैंडिंग समय पर नहीं हो पाती थी, जिसके कारण कई बार यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। जानकारी के मुताबिक, राजाभोज एयरपोर्ट पर कटेगरी-2 लैंडिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसकी ग्राउंड टेस्टिंग भी की जा चुकी है। एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि अब सिर्फ कटेगरी-2 की मंजूरी का इंतजार है। डीजीसीए की परमिशन के बाद इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा।



गौरतलब है कि राजाभोज एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां कटेगरी-2 का लैंडिंग सिस्टम होगा, जिससे खराब मौसम में भी उड़ानें एयरपोर्ट पर आसानी से लैंडिंग कर पाएंगी।

एयर एंबुलेंस की जानकारी के लिए अलग काउंटर मेडिकल इमरजेंसी के लिए समय पर उचित जानकारी न मिल पाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के

लिए अब एयरपोर्ट पर अलग काउंटर स्थापित किया जाएगा। राजधानी भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पर मौजूद सुविधाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद आलोक शर्मा ने यह बात कही। इस मौके पर सांसद शर्मा ने एयरपोर्ट विस्तार को लेकर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए जा रहे एराइवल और पार्किंग स्थल के काम को देखा। इस दौरान सांसद शर्मा ने एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी को कहा कि यह सुनिश्चित करें कि काम गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में पूरे हों। यात्री सेवा और सुविधा के मामले में राजाभोज नंबर 1 पर हो, ऐसे प्रयास करें। नए बन रहे एराईवल को पूर्ण करने के लिए दिसंबर तक की डेड लाइन तय की है।
प्रति घंटा पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 1200
एयरपोर्ट डायरेक्टर ने सांसद शर्मा को जानकारी दी कि अभी एयरपोर्ट पर प्रति घंटा पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 1200 के लगभग है। वहीं विस्तारीकरण कार्यों के पूर्ण होने के बाद एयरपोर्ट पर पैसेंजर कैपेसिटी 3000 प्रति घंटा हो जाएगी। भविष्य को

ध्यान में रखकर यह काम हो रहे हैं। इससे भोपाल ही नहीं भोपाल के आसपास के लोगों को हवाई यात्रा करने में आसानी हो जाएगी।
रन वे का विस्तार जरूरी
सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए रन वे का विस्तार जरूरी है। इसकी स्टैंडर्ड लंबाई 3300 मीटर करने का प्रस्ताव बनाएं। अभी भोपाल एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई 2700 मीटर है। सांसद शर्मा ने कहा कि भोपाल से रीवा व भोपाल से दतिया के लिए फ्लाइट जल्द शुरू हो इसका शेड्यूल बनाएं। भारत सरकार और विमानन विभाग का प्रयास है कि जनता को सुविधाओं का लाभ मिले।
एयरपोर्ट परिसर में किया पौधारोपण
इस अवसर पर सांसद शर्मा ने एयरपोर्ट परिसर में ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपण किया। इस दौरान एयरपोर्ट निदेशक रामजी अवस्थी, सीआईएसएफ के डिप्टी कमाण्डेंट मान सिंह, महाप्रबंधक संचार आलोक त्रिपाठी, संयुक्त महाप्रबंधक (एटीसी), सुनील कुमार बांसोड़ सहित एयरपोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने वाले दो युवकों पर रासुका

सिटी चीफ भोपाल ।
भोपाल। भोपाल के बैरसिया में एक नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने वाले दो युवकों पर कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिंह ने रासुका की कार्रवाई की है। इस मामले में एक दिन पहले गुरुवार को बैरसिया में जमकर हंगामा हुआ था। कलेक्टर सिंह ने कार की बोनट पर खड़े होकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसके बाद प्रदर्शन करने वाले माने थे। इसके दूसरे ही दिन अब आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है।



अंदर एसडीएम कार्यालय में दे सकते हैं।

मार्फ फोटो वायरल करने की भी दी थी धमकी

पुलिस के अनुसार, 17 साल की पीड़िता बैरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला अरमान मंसूरी नाबालिग को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजता था। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पीड़िता को फॉलो कर भदे कमेंट्स करता था। जबरन बातचीत करने का दबाव बनाता था। लड़की बात करने से इनकार करती थी, अथवा रिप्लाई नहीं करती तो उसके मार्फ फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। इससे तंग युवती ने मामले की जानकारी मां को दी। मां ने पिता को बताया। पिता उसके लेकर बुधवार को थाने आए। इस

मामले में कुल चार आरोपी बताए जाते हैं।

हिंदू संगठनों ने किया था बैरसिया थाने का घेराव

11वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के इस मामले में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने बैरसिया थाने का घेराव किया था। इखड विधायक विष्णु खत्री भी मौके पर पहुंचे थे। हंगामा बढ़ता देख कलेक्टर सिंह मौके पर पहुंचे और कार के बोनट पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को समझाया था। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। कलेक्टर ने कहा था कि जो भी शिकायत है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के बाद आपको बताएंगे भी। इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेंगे, जिससे भविष्य में कोई ऐसा अपराध न करें। जल्द ही स्कूलों के पास की गुमटियों को भी हटाएंगे। अब आप लोग रुकना चाहते हैं तो रुकें, नहीं तो घर चले जाएं।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने एसपी को घेरा

भोपाल के बैरसिया कस्बे में नाबालिग को मैसेज करने और फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई में देरी पर भोपाल ग्रामीण के एसपी प्रमोद सिन्हा पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। भोपाल में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा- हिंदू समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई में लापरवाही की है वह गलत है। वास्तविकता में भोपाल (ग्रामीण) एसपी जो है वह अपराधी हैं। उन्होंने अपराध किया है। वे अपराधियों को शरण देते हैं। अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती तो समाज को इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं समाज को बहुत बधाई देता हूं।
अपराधियों से दोस्ती करना बंद करें एसपी
रामेश्वर शर्मा ने कहा- मैं फिर, एसपी को बता देना चाहता हूं कि अपराधियों से दोस्ती करना बंद करो, कार्रवाई करो। तुम्हारे संपर्क में कसाई भी हैं, तुम्हारे संपर्क में छेड़खानी करने वाले भी हैं। ध्यान रखना यह भाजपा की मोहन यादव की सरकार है। बिरयानी खाने वालों की नहीं है। बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी तो टीआई नहीं, एसपी भी हटेगा।

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल । भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो (डॉ) के जी सुरेश का कार्यकाल आगामी 15 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। उनके जगह पर राज्य सरकार ने जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को प्रभार सौंपा है। वे प्रो. के जी सुरेश का स्थान लेंगे। दरअसल, शुक्रवार दोपहर बाद मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी करते हुए यह कहा कि प्रो. (डॉ) के जी सुरेश कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का कार्यकाल 15/09/2024 को समाप्त होने से नियमित कुलगुरु की नियुक्ति तक कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार डॉ. सुदाम खाड़े आयुक्त, जनसंपर्क विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से कार्यभार सौंपा जाता है। बता दें कि के जी सुरेश ने इससे पहले, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। भारत के



सार्वजनिक समाचार प्रसारक डीडी न्यूज के वरिष्ठ परामर्श संपादक, एशियानेट न्यूज नेटवर्क के संपादकीय सलाहकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य राजनीतिक संवाददाता और डालमिया भारत इंटरप्राइजेज के समूह मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है।
2006 बैच के अफसर हैं सुदाम खाड़े
सुदाम खाड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा 2006 बैच के अफसर हैं। इन्हें दूसरी बार एमपी में जनसंपर्क की कमान मिली है। पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे

तब भी जनसंपर्क आयुक्त रहे थे और अब डॉ. मोहन यादव की सरकार ने फिर मौका दिया है। इससे पहले उन्हें ग्वालियर संभाग का आयुक्त बनाया गया था। सुदाम खाड़े दो बार मध्य प्रदेश के 2 जिलों के कलेक्टर रहे, सीहोर और भोपाल की इन्होंने कमान संभाली थी। इसके बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कमिश्नर के पद पर भी रह चुके हैं। तत्कालीन शिवराज सरकार में जिस विभाग में यह रहे थे हमेशा उनकी तारीफ होती रही है। अब इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कमान सौंपी गई है।

विभाग हुआ सख्त, लार्वा मिलने पर लगाया जा रहा स्पॉट फाइन

लगातार बारिश के चलते भोपाल में डेंगू का प्रकोप

सिटी चीफ भोपाल ।
भोपाल। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी भोपाल में जगह-जगह पानी का भराव हो रहा है जिस वजह से डेंगू, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी लगातार पनप रहे हैं। मलेरिया विभाग, नगर निगम और एंबेड परियोजना मिलकर शहर में जगह-जगह लार्वा सर्वे कर रहे हैं और लार्वा मिलने पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। शुक्रवार को लार्वा पाए जाने पर स्पॉट फाइन के रूप में होटल आर्किड पैलेस, और होटल वेस्टर्न सहित कई जगह में 3500 रुपए का जुर्माना किया गया। वहीं नारायण स्कूल 5000 का जुर्माना कोलार क्षेत्र में किया गया और समझाइ दी गई कि दोबारा लार्वा मिलता है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर योजना के डॉ.संतोष भार्गव ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी एवं प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी डॉ अर्चना मिश्रा के मार्गदर्शन में शहर में संयुक्त रूप से लार्वा सर्वे, फॉरिंग और बुखार का सर्वे किया गया। साथ ही डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि डेंगू नियंत्रण में सभी लोगों का



आवश्यक सहयोग जरूरी है, चूंकि डेंगू का मच्छर घर के अंदर एवं बाहर साफ पानी में पनपता है, अतः पानी को हर सप्ताह बदले की जानकारी लोगों को दी जा रही है।
तालबों में डाली गंबूसिया मछली
जिला वीबीडी सलाहकार रुचि सिलाकारी ने बताया कि नगर निगम के साथ मलेरिया की टीम सतत रूप से डेंगू नियंत्रण हेतु कार्य कर रही है, और लार्वा पाए जाने पर स्पॉट फाइन भी जारी है। टीम के द्वारा क्षेत्र के समस्त तालाब, बड़े आदि एम गंबूसिया मछली डाली गई। लार्वा पाए जाने वाले घरों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों को बताया कि आगे से किसी भी

जगह लार्वा नहीं पनपना चाहिए, जिससे की बीमारी फैले। विभिन्न क्षेत्रों में जिला मलेरिया कार्यालय, एंबेड एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से लार्वा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। और लार्वा पाए जाने पर नगर निगम द्वारा जुमाने की कार्यवाही की जा रही है, सभी से अपील है अपने घर एवं घर के आसपास मच्छर नहीं पनपने दे, पानी को ढककर रखे , छत के उपर पानी की टंकी में ढक्कन अवश्य लगाएं। इस दौरान समस्त जोन में जोन प्रभारियों नगर निगम, मलेरिया एवम एंबेड टीम के द्वारा समस्त घरों में लोगों को समझाइश दी एवं लार्वा सर्वे किया ।

इन्गू में प्रवेश के लिए छात्रों को एक और मौका, बढ़ाई गई तारीख

सिटी चीफ भोपाल ।
भोपाल। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय (इन्गू) ने छात्रों को प्रवेश के लिए एक और मौका दिया है। यूजी, पीजी, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार फिर इन्गू ने तारीख को आगे बढ़ा कर 20 सितंबर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले प्रवेश की आखिरी तारीख 10 सितंबर थी। इन्गू में एडमिशन के लिए छात्र एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से इन्गू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 2024 के लिए इन्गू आवेदन पत्र को पूरा करते समय, उम्मीदवारों को अपना नाम और अन्य विवरण ठीक इस प्रकार से देना होगा जैसा कि उनके शैक्षिक दस्तावेजों में दिखाई देता है।
बीटेक में दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन शुरू तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) द्वारा दो राउंड और सीएलसी का प्रथम राउंड पूरा होने के बाद भी अब तक आधी सीटें खाली हैं। इन खाली पड़ी सीटों को प्रवेश के लिए छात्र 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं 15 सितंबर



को सुबह 10.30 बजे ऑफलाइन माध्यम से कॉलेज में उपस्थित होकर छात्रों को प्रवेश लेना होगा। बता दें कि प्रवेशित छात्रों को इंटरनल ब्रांच परिवर्तन का अवसर भी दिया गया था। इस प्रक्रिया में शामिल होने करीब 4000 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से विभाग ने 1990 छात्रों की ब्रांच बदलकर सीट अलॉट की हैं। दो लाख सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी

डीटीई द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी कोर्सों की करीब दो लाख सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक में प्रवेश के लिए दोनों राउंड में 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके बाद सेकंड राउंड में 21 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने चाईस लॉक की थी।

खेल अकादमियों में पैरा खिलाड़ियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण



सिटी चीफ भोपाल ।
भोपाल। पिछले दिनों पेरिस में खेले गए पैरालिंपिक-2024 में कांस्य पदक जीतने वाले मप्र के लाडुले सपूत कपिल परमार शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तात्या टोपे स्टेडियम में कपिल से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और पैरालिंपिक गेम्स में पदक जीतने पर

बधाई दी। इस मौके पर खेल मंत्री सारंग ने पैरा खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा की। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश की सभी खेल अकादमियों में पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पैरा खिलाड़ियों के लिए नौकरी के साथ विशेष बजट का भी प्रविधान किया जाएगा। गौरतलब है कि कपिल परमार पैरालिंपिक जूडो में पदक जीतने वाले

देश के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने मप्र राज्य जूडो अकादमी में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने 28 अगस्त से 80 सितंबर तक पेरिस में खेले गए पैरालिंपिक में पुरुषों की जे1-60 किग्रा श्रेणी में कांस्य पदक के मुकाबले में ब्राजील के एल्लिटन डी ओलीवेरिया को हराकर यह सफलता प्राप्त की थी।
हादसे में खो दी थी आंखों की रोशनी
कपिल मूलतः सीहोर के निवासी है।

वर्ष 2009-10 में करंट लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कपिल 80 प्रतिशत ब्लांड हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जूडो को खेलना प्रारंभ किया था। उन्होंने पहली बार पैरालिंपिक में हिस्सा लिया था। कपिल अब तक 17 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 08 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 अंतरराष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं।

सम्पादकीय

आखिर क्यों बढ़ाया गया

‘आयुष्मान भारत’ का दायरा?

केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना का नया विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष पांच लाख तक का अलग से टॉप-अप कवर मिलेगा।

केंद्र सरकार ने लोगों के सेहत से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान भारत योजना के लाभ के दायरे को बढ़ाया गया है। अब इस योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक हर बुजुर्ग को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बुधवार को कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने पर मुहर लगाई। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यू-एच-सी) के उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी पीछे न छूटे। योजना में दो घटक शामिल हैं- पहला स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय)। 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर के विस्तार की घोषणा अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। नए फैसले से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज मिल सकेगा। इसका लक्ष्य छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर देना है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल कर लिया है। केंद्र के नए फैसले का लाभ छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना का नया विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष पांच लाख तक का अलग से टॉप-अप कवर मिलेगा। हालाँकि, इस टॉप-अप कवर परिवार के ऐसे अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य करीब 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराना है। मौजूदा समय में उन व्यक्तियों को योजना का लाभार्थी माना जाता है जो भारत सरकार के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटाबेस की विशेष श्रेणियों में शामिल हैं। दरअसल, 55 करोड़ लाभार्थियों की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर तय की गई थी। आयुष्मान भारत पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है। इसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। योजना में समय-समय पर कई लाभार्थी वर्ग जोड़े जा चुके हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने 2011 की जनसंख्या की तुलना में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 11.7७ को देखते हुए जनवरी 2022 में योजना के तहत लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ से बदलकर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया। देशभर में काम करने वाली 37 लाख आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को लाभ देने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब योजना देशभर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि इन नागरिकों की आय का पैमाना अब खत्म हो गया है। यह योजना प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस कवर प्रदान करती है। 5,00,000 रुपये का लाभ फैमिली फ्लोटर के आधार पर है, जिसका मतलब है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्य कर सकते हैं।

हिंदी साहित्य को जीवित रखने में थिएटर की भूमिका महत्वपूर्ण, छोटा पर्दा कर सकता है बड़ा काम

जब मैं अपने कला के सफर को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि एक अभिनेत्री और निर्देशक के रूप में मुझे भारत की साहित्यिक समृद्धि का जश्न मनाने के कई अवसर मिले। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में दिल्ली स्थित थिएटर समूह संभव ने मुझे समाज को आईना दिखाने वाली कई बेहतरीन कहानियों का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। मैं कहूँगी कि थिएटर ने हिंदी साहित्य को जीवित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई क्लासिक नाटक वास्तव में मुंशी प्रेमचंद, भीष्म साहनी और जयशंकर प्रसाद जैसे हिंदी साहित्यकारों की कृतियों से प्रेरित हैं। थिएटर ने साहित्य को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। जब मुझे साहित्यिक संकलन कोई बात चले का निर्देशन करने का अवसर मिला तो मैंने भी इस उम्मीद के साथ सआदत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई की कालजयी कहानियों को चुना कि ये कहानियां युवाओं के बीच उनकी साहित्यिक इतिहास को फिर से जानने की इछा पैदा करेंगी। एक अभिनेत्री के रूप में भी, चाहे वह मंच हो या स्क्रीन, मुझे महान लेखकों द्वारा लिखे गए किरदारों को निभाने का अवसर मिला है। यहां तक कि भारत के पहले टेलीविजन सोप ओपेरा हम लोग, जिसमें मैंने अभिनय किया था, उसे

साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। मेरा किरदार बड़की हर उस भारतीय लड़की का प्रतीक बन गया, जिसे रंगभेद के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस शो की सफलता ने यह साबित किया कि भाषा एक शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी का माध्यम हो सकती है। मैं साग पीट नाटक को लेकर भी बेहद गर्व महसूस करती हूँ, जिसे मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक, भीष्म साहनी ने लिखा था। इस नाटक के 100 से अधिक शो करना मेरे लिए एक बेहद संतोषजनक रचनात्मक अनुभव था। अगर मैं अपने पसंदीदा कहानीकारों की बात करूँ तो राजेंद्र सिंह बेदी एक और दिग्गज हैं, जिनके काम ने कई फिल्मों और थिएटर प्रस्तुतियों को प्रेरित किया है। इस्मत चुगताई और मंटो की उर्दू कृतियों को भी कई बार नाटकों और फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। जहां तक टोबा टेक सिंह, हतक, ईदगाह, गुल्ली डंडा, जम्माद काई और एक फिल्म कथा के संदर्भ कहानियों की बात है तो मुझे बेहद खुशी है कि इन्हें उस समय संजोकर रखा गया जब हम अपने ही साहित्यिक धरोहर से दूर होते जा रहे हैं।

लोग थिएटर देखने के लिए बहुत कम आते हैं और टेलीव्हे नई पीढ़ी और आम जनता को, बिना बाहर गए, अपने घर पर ही भारतीय साहित्य की सुंदरता को जानने में

जिस हिन्दी का ऐसा इतिहास रहा हो, जिसे विनोबा जैसे संघर्षशील और त्यागी-तपस्वी व्यक्ति ने अपनी भाषायी तपस्साधना का माध्यम बनाया हो, उसे स्वाधीनता के बाद तेजी से विस्तारित होना चाहिए था। वह विस्तारित तो हुई, लेकिन उस रूप में स्थापित नहीं हुई, जिस रूप में स्वाधीनता सेनानियों ने सोचा था। राजभाषा की उसे पदवी तो मिली, लेकिन वह रस्मी ही साबित हुई। राजभाषा की भूमिका सरकारी दफ्तरों में सिर्फ हिन्दी पखवाड़े या महीने में कार्यालयों में रस्मी निबंध, कहानी और कविता प्रतियोगिता आयोजित करने और किसी हिंदी विद्वान को बुलाकर उंचे और उबते कर्मचारियों के बीच भाषण कराने तक सीमित रह गई।

हिन्दी की जब भी चर्चा होती है, दो तरह के भाव आते हैं। इसे लेकर पहला भाव उत्साह और गर्वबोध वाला होता है। हिन्दी के क्षितिज के लगातार हो रहे विस्तार और उसके गर्वीले अतीत को लेकर हिन्दीप्रेमी जहां उत्साह से भर उठते हैं, वहीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े गुलामी की मानसिकता वालों के चेहरे पर विद्रूप और व्यंग्यभरी मुस्कान चिपक जाती है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों के राजनीतिज्ञ तो हिन्दी से अछूत जैसा व्यवहार करने में स्वयं जहां गर्वबोध का अनुभव करते हैं, वहीं अपने समर्थकों को हिन्दी को दुश्मन की तरह मानने के लिए उकसाने में भी पीछे नहीं रहते। इसके बावजूद हिन्दी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, विशेषकर आमजन की बोली-बानी के रूप में यह स्थापित होती जा रही है। इतने सारे विरोध के बावजूद और अड़ों के बावजूद हिन्दी अगर बढ़ती नजर आ रही है तो मानना पड़ेगा कि उसमें कुछ बात जरूर है। हिन्दी के इस प्रभावी हथ्त्र पर इकबाल की पंक्तियां याद आना स्वाभाविक है-

कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौर-ए-जमाँ हमारा ॥

हिन्दी की राह में आजादी के पहले ज्यादा बाधाएं नहीं थीं। इसकी शायद यह बड़ी वजह रही कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अगुआ महात्मा गांधी स्वयं हिन्दी के हिमायती थे। उनके पहले केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक जैसी हस्तियां भी देश के हृदयों को नजदीक लाने में हिन्दी की सामर्थ्य को पहचान चुके थे। इसीलिए गैर हिन्दीभाषी होने के बावजूद उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की केंद्रीय भाषा हिन्दी को बनाने की कोशिश की और भावी भारत की भाषायी जरूरतों के लिहाज से हिन्दी को तैयार करने की कोशिश भी की। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य हिन्दी को भावी भारत की भाषायी जरूरत के लिहाज से न सिर्फ तैयार करना था, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच मजबूत सेतु के रूप में स्थापित करना भी था। हिन्दी इस दिशा में आगे बढ़ती रही। कांग्रेस के दस्तावेज भले ही अंग्रेजी बनते रहे, लेकिन बहसों और उसके वार्षिक अधिवेशनों की भाषा हिन्दी ही

मदद कर रहा हैं।

महामारी ने निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत और रचनात्मक जीवन को बदल दिया और थिएटर कलाकारों के लिए अपने काम को घर बैठे दर्शकों तक पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। यहां तक कि महामारी के बाद भी लोग टिकट खरीदकर थिएटर या फिल्म समकने में मदद कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह जैसी कहानी कन्नड़ या तेलुगू में अनुवादित होने पर भी विश्वाषन की त्रासदी और लाखों लोगों की मनोवृत्ति पर विभाजन के प्रभाव की याद दिलाती रहेगी। मंटो की हतक महिलाओं के अमानवीकरण और उनकी अखंडता के बारे में है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब इसे पहली बार लिखा गया था। हरिशंकर परसाई की एक फिल्म काथ्य जनप्रिय सिनेमा पर एक व्यंग्य है, और किसी भी भाषा में इसका हास्य और विडंबना दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करेगी।



रही। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद हिन्दी के इस प्रभाव को सुभाष चंद्र बोस ने भी समझा और बाकायदा हिन्दी सीखी। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते पार्टी के वार्षिक अधिवेशन को उन्होंने हिन्दी में ही संबोधित किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के आर्काइव में आज भी सुरक्षित है। उनकी मीठी हिन्दी एक तरह से मोहती है। उसे सुन लगता है कि स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी किस तरह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी।

जिस हिन्दी का ऐसा इतिहास रहा हो, जिसे विनोबा जैसे संघर्षशील और त्यागी-तपस्वी व्यक्ति ने अपनी भाषायी तपस्साधना का माध्यम बनाया हो, उसे स्वाधीनता के बाद तेजी से विस्तारित होना चाहिए था। वह विस्तारित तो हुई, लेकिन उस रूप में स्थापित नहीं हुई, जिस रूप में स्वाधीनता सेनानियों ने सोचा था। राजभाषा की उसे पदवी तो मिली, लेकिन वह रस्मी ही साबित हुई। राजभाषा की भूमिका सरकारी दफ्तरों में सिर्फ हिन्दी पखवाड़े या महीने में कार्यालयों में रस्मी निबंध, कहानी और कविता प्रतियोगिता आयोजित करने और उबते कर्मचारियों के बीच भाषण कराने तक सीमित रह गई। हिन्दी दिवस पाखंड बनकर रह गया। अच्छी बात यह कह सकते हैं कि इस बहाने सरकारी कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों को कुछ नगद रकम बतौर पारितोषिक मिल जाती है, और बाकी कर्मचारियों को मिठाई और नाश्ता आदि और फिर हिन्दी की पूरे वर्षभर के लिए राजभाषा के रूप में इतिश्री हो जाती है। राजभाषा के नाम पर इस रस्म को आयोजित होने की परंपरा को विकसित करने में संविधान सभा के उस विधान की बड़ी भूमिका रही, जिसके तहत हिन्दी को संविधान लागू होने से पंद्रह वर्षों तक के लिए टाल दिया गया। कहा गया कि इतने दिनों में हिन्दी राजकाज में स्थापित अंग्रेजी का स्थान लेने लायक हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी समर्थकों, हिन्दी विरोधी कहना ज्यादा समीचीन होगा, ने हिन्दी के खिलाफ षड्यंत्र जारी रखा। इसके लिए

उन्होंने अंग्रेजी को हिन्दी की तुलना में ज्यादा गंभीर और प्रभावी रूप से स्थापित किया। इतना नहीं, इस बीच हिन्दीतर दूसरी भारतीय भाषाओं के मन में हिन्दी को लेकर लगातार जहर भरा जाता रहा। इसमें अंग्रेजी शिक्षा और उसके जरिये मिलने वाली सुख-सुविधाएं और बेहतर नौकरियों ने बड़ा योगदान दिया। अगर आजादी के तुरंत बाद हिन्दी को लागू कर दिया जाता और हिन्दी को विकसित करने के तर्क को परे सरका दिया गया होता तो आज हिन्दी कुछ उसी तरह स्थापित होती, जैसे इंडोनेशिया और तुर्की में हुआ। इसे संयोग ही कहेंगे कि भारत से ठीक दो वर्ष पहले 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया डच शासन से मुक्त हुआ था। तब तक इंडोनेशिया के राजकाज की भाषा डच होती थी। लेकिन आजादी मिलते ही इंडोनेशिया के शासक सुकर्णो ने तुरंत अपनी भाषा ‘बहासा इंडोनेशिया’ को लागू कर दिया। कुछ इसी तरह 23 अक्टूबर 1923 को जब आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई, तब वहां के स्वाधीनता सेनानी और शासक कमाल अतातुर्क ने तत्काल तुर्की भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में लागू कर दिया। अगर भारत में भी कुछ हिन्दी के साथ ऐसा ही हुआ होता तो निश्चित तौर पर इतिहास और परिदृश्य दोनों अलग होते। स्वाधीन भारत से एक और गलती हुई है। वैसे इसे गलती मानें या जानबूझकर रचा गया हिन्दीविरोधी षड्यंत्र कहें। स्वाधीन भारत की नौकरशाही की भाषा अंग्रेजी ही रही। या यूं कहें कि हिन्दी या भारतीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए ऐसी राह तैयार की गई कि वे ही नौकरशाही में आ सकें। भारतीय भाषाओं को संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए आंदोलन चला तो उसके दबाव में भारतीय भाषाएं आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनीं तो लेकिन परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया का ढांचा ऐसा बना रहा कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र ही ज्यादा चुने जाते रहे। हिंदी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित इक्का-दुक्का विद्यार्थी अगर नौकरशाही में प्रवेश पाने में सफल रहे भी तो उनकी स्थिति ‘नक्कारखाने में तूती की

आवाज’ जैसी रही। नरेंद्र मोदी के उभार और मोदी-शाह की जोड़ी के हिन्दी प्रेम के चलते नौकरशाही में हिन्दी के प्रति रूझान दिखा। नौकरशाही की भाषायी सोच में परिवर्तन आता दिखा भी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वह नौकरशाही की रणनीतिक चाल रही। नौकरशाही ने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम का संकेतभर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। हिन्दी और भारतीय भाषाएं राजकाज में एक बार फिर पीछे हो गई हैं। अंग्रेजी अब भी नौकरशाही और राजकाज में वर्चस्व बनाए हुए है। उसके मनोभाव उसके इरादे को एक बार फिर जाहिर करने लगे हैं। वह एक बार फिर हिन्दी पर अंग्रेजी को ही उपर रखने लगी है। राजकाज एक बार फिर पुरानी पट्टी पर कम से कम भाषायी लिहाज से लौटने लगा है। हिन्दी को लेकर ऐसा रूख नौकरशाही अगर दिखाती है तो इसकी वजह हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच की आपसी खींचतान के साथ ही शासन की रस्मी भाषा नीति भी है।

हिन्दी की राह में यूं तो कई बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा शासन में उसकी उपेक्षा और अंग्रेजीदां नौकरशाही का वर्चस्ववादी रवैया है। इस रवैये का नुकसान ज्यादातर जमीनी नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। क्योंकि उनकी समस्याओं को सही मायने में समझने वाली ब्यूरोक्रेसी ही नहीं है। यह मोटा तथ्य है कि किसी व्यक्तिया इलाके की समस्याओं को वही गहराई से समझ सकता है, जो उस व्यक्ति की अपनी भाषा में सोचता हो, उस इलाका विशेष की माटी की संस्कृति से जुड़ा हो। लेकिन इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि ज्यादातर नौकरशाही ऐसी सोच से कोसों से दूर है। इसीलिए हिन्दी समेत भारतीय भाषाएं राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी से कोसों पीछे हैं। उच्च स्तर पर प्रभाव के लिहाज से भी हिन्दी का स्थान कुछ खास नहीं है। हिंदी दिवस पर क्या हम इस नजरिये से हिन्दी की स्थिति को देखेंगे? वक्त आ गया है कि इस सवाल से गंभीरता से जूझा जाए।

अरुणाचल में खिलती खिलखिलाती हिंदी व्यावसायिक स्वीकार्यता की एक मिसाल

शाम का समय, पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भीड़-भाड़ वाले गंगा मार्केट में गुजरते हुए स्थानीय उच्चारण में लोगों द्वारा शुद्ध हिंदी में बातचीत सुनकर एक सुखद आश्चर्य हुआ। पीछे मुड़कर देखा, तो तीन-चार महिलाएं और बच्चे आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे। पता चला कि यहां के लोग अपने घर-परिवारों में तो देखने जाने के लिए कम समय निकाल पा रहे हैं। यही कारण है कि अब हमें छोटे पर्दे की जरूरत है, ताकि अछे कंटेंट को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सके। मैं इस बात की भी सराहना करती हूँ कि कैसे विभिन्न भाषाओं में नाटकों के अनुवाद और रूपांतरण दर्शकों को भारत की विविध संस्कृतियों से फिर से जोड़ रहे हैं और उन्हें हमारे मूल मूल्यों और भावनाओं की वैश्विकता को समकने में मदद कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह जैसी कहानी कन्नड़ या तेलुगू में अनुवादित होने पर भी विश्वाषन की त्रासदी और लाखों लोगों की मनोवृत्ति पर विभाजन के प्रभाव की याद दिलाती रहेगी। मंटो की हतक महिलाओं के अमानवीकरण और उनकी अखंडता के बारे में है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब इसे पहली बार लिखा गया था। हरिशंकर परसाई की एक फिल्म काथ्य जनप्रिय सिनेमा पर एक व्यंग्य है, और किसी भी भाषा में इसका हास्य और विडंबना दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करेगी।



समझ-बोल नहीं पाते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने भाषायी एकरूपता स्थापित करने के लिए सभी स्कूल-कॉलेजों में हिंदी को लागू किया। इसके अलावा, चीन के आक्रमण के उपरंत इन क्षेत्रों में तेजी से हुए विकास कार्यों के कारण यहां अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में हिंदी व अन्य भाषा-भाषी लोग आए और धीरे-धीरे, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने असमिया का स्थान ले लिया। स्थानीय लोगों ने भी सहर्ष एवं स्वेच्छा से हिंदी को अपना लिया है और हिंदी यहां मुख्य संपर्क बोली नहीं, बल्कि भाषा बन गई है। यहां से हिंदी की कई पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं।

वर्ष 1977 में भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा निर्देशित पहली फिल्म %मेरा धर्म-मेरी मां% हिंदी में ही बनी थी, जो अरुणाचल की अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म है। यहां से हिंदी फिल्मों का निर्माण भी हो रहा है और वे लोकप्रिय भी हो रहे हैं। पूर्वोत्तर 2में अरुणाचल ही एक ऐसा राज्य है, जहां संचार प्रणाली में पूर्णतया हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।

बेशक अंग्रेजी यहां की आधिकारिक राजभाषा है, जो औपचारिक दस्तावेजी कागजों तक ही सीमित है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज के लिए

यहां हिंदी भाषा का ही बहुधा प्रयोग किया जाता है। नतीजतन हिंदी व्यावहारिक भाषा के रूप में पूरे अरुणाचल में स्वीकार्य भाषा बन गई है। यहां हिंदी का प्रचार-प्रसार भाषा के रूप में नहीं, बल्कि बोली के रूप में अधिक हो रहा है। निस्संदेह अरुणाचल में हिंदी तेजी से अपने पांव पसार रही है, लेकिन यहां की क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग काफी कम हो गया है तथा कई स्थानीय जनजातीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए हमें हिंदी को बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय भाषाओं और संस्कृति को भी बचाने का प्रयास करना होगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वम लगातार बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों का किया जा रहा निरीक्षण

पुलिस प्रशासन द्वारा दिये गये लोगों को खाने के पैकेट

आदित्य द्विवेदी । सिटी चीफ भिण्ड, पुलिस अधीक्षक डा. असित यादव द्वारा जलभराव वाले क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर जायजा लिया गया एवं सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लगातार जलभराव वाले स्थानों का भ्रमण करें तथा जलभराव की स्थिति अथवा आशंका होने पर तुरंत होमगार्ड, एसडीईआरएफ एवं रेस्क्यू टीम से समन्वय स्थापित करें। इसी क्रम में ग्राम कछपुरा एवं ग्राम भारौली के जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया एवं भ्रमण के दौरान सभी लोगों को नदी एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने तथा आसपास जलभराव की स्थिति होने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई। थाना अमायन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कछपुरा में सिंध नदी का पानी भर जाने से करीब



100 परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। थाना अमायन पुलिस जवानों द्वारा इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा इन परिवारों को खाना के पैकेट उपलब्ध कराए गये। इनके द्वारा निर्मित अस्थाई निवासी की पुलिस द्वारा निगरानी एवं हर संभव मदद की जा रही है। भिण्ड पुलिस द्वारा नदी से सटे गाँवों को खाली करा लिया गया है एवं नदी से लगे सभी गावों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी से दूर रहने एवं सुरक्षित

स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई। पुलिस अधीक्षक की आम जनता से अपील। 1. नदी, तालाबों एवं जलभराव वाले स्थानों से स्वयं एवं अपने बच्चों को दूर रखें। 2. आसपास जलभराव होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। 3. किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल 100 एवं पुलिस कंट्रोल रूम नं0 93434-84416 पर सूचित करें।

सब्जी मंडी के दरवाजे पर किसके संरक्षण में होती है अवैध वसूली, लोगों से आए दिन अभद्रता...

वाहन चालकों से लेते हैं दस रुपए बदले में नहीं देते हैं कोई रसीद...

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, स्मार्ट सिटी सतना में जंगलराज हावी होता जा रहा है, शायद यही वजह है कि जहां देखो वहीं लोगों से अवैध वसूली करने वालों का गिरोह काम कर रहा है। आखिर किसके संरक्षण में सतना शहर के भैंसाखाना क्षेत्र में संचालित सब्जी मंडी गेट पर वाहन चालकों से अवैध वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि डंके की चोंट पर दस रुपए लेने वाले गुर्गे बदले में वाहन पार्किंग के कोई रसीद उपलब्ध नहीं करवाते हैं। जब कभी कोई इस अवैध वसूली को लेकर आवाज उठाता है तो वसूलीवाज गिरोह के सदस्य अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं। आए दिन सब्जी मंडी गेट पर विवाद की घटनाएं अवैध वसूली के कारण सामने आती रहती है।



मंडी परिसर के दो अलग-अलग हिस्सों में तैनात रहकर ठेकेदार के गुर्गे अवैध वसूली को मुकम्मल करते हैं। बताया जाता है कि सब्जी मंडी के दोनों गेट पर चार से पांच की संख्या में गुर्गे तैनात रहकर वसूली करते हैं। वाहन पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली इस बात का प्रमाण है कि सतना नगर निगम में कैसा रामराज्य चल

रहा है? बताया जाता है कि सब्जी मंडी परिसर के अंदर सब्जियों की दुकान लगाने वाले लोगों से भी गैंग अवैध वसूली को मुकम्मल करती है। आखिर सतना नगर निगम में ऐसा कौन सा अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि है जिसके संरक्षण में सब्जी मंडी में लोगों से अवैध वसूली को सफल बनाया जा रहा है।

चित्रकूट विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक संपन्न

चित्रकूट डेवलपमेंट अथॉरिटी का हुआ गठन



उमेश कुशवाहा। सिटी चीफ सतना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने प्राचीन मुखारविंद से गौरिहार मंदिर तक पैदल विजित किया, मंदाकिनी तट पर पहुंचकर विकास कार्यों का लिया जायजा, एडीएम को बयान, चित्रकूट में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं लेकिन उनमें एकरूपता नहीं आ रही थी, मध्य प्रदेश सरकार ने अब चित्रकूट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। अब जो चित्रकूट

में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं अब उनको हम लोग एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे. सभी विभागों का एक साथ सामंजस के साथ कार्य किया जाएगा भरत घाट पर निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम ने बताया कि भरतघाट में सुंदरीकरण और घाट निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिसका निरीक्षण करने हम पहुंचे हैं मंदाकिनी में कैसे नालों का गंदा पानी जाने से रोका जाए यह हमारा प्रयास है उसी का निरीक्षण

किया जा रहा है,साथ ही सीवर लाइन के ठेकेदार को 2 महीने का समय बढ़ा दिया गया है क्योंकि दीपावली का पांच दिवसीय मेला होता है जहां पर उनके द्वारा सड़के बनाई गई है वहां पर अच्छे ढंग से सड़कों को बनाया जाए जिससे कि वह सड़के धंसे नहीं, मरम्मत की गई सभी सड़के जगह-जगह पर धंस रही हैं जिसको लेकर सीवर लाइन ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं-- स्वप्निल वानखेड़े एडीएम.

श्रद्धालुओं ने मनाई तेजाजी महाराज की जयंती

भक्ति गीतों पर झूमते श्रद्धालुओं का गुलाल और फूलों से किया गया स्वागत



निशान चढ़ाए। सैकड़ों लोगों ने मन्नत मांगी और जिन लोगों की मन्नत पूरी हुई उन्होंने तेजाजी महाराज को छतरी चढ़ाई। वहीं इस जुलूस का विभिन्न मार्गों पर भव्य स्वागत भी किया गया। इसके अलावा चल समारोह में भक्ति गीतों पर श्रद्धालू झूमते हुए चल रहे थे, जिनका गुलाल और फूलों से स्वागत किया गया।

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, बादशाही पुल स्थित तेजादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा शुक्रवार को तेजा जयंती कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर के प्रमुख मार्गों से एक चल समारोह भी निकाला गया जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। चल समारोह की शुरुआत बादशाही पुल से हुई जो भीरकला, आजाद चौक, नईसडक, नाग नागिनी रोड, सोमवारिया बाजार होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने तेजा जी महाराज को छतरी स्वरूप चढ़ाया।

गांव गांव हो रही है पैकारी

लाचार है आबकारी विभाग, शराब ठेकेदारों ने कर राखी है सेटिंग

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, पूरे जिले के शराब माफियाओं के द्वारा निर्धारित दुकानो से शराब की सीमित बिक्री और कम मुनाफा के चलते ठेकेदारो की ओर से ठेकेदारो ने अपने अपने क्षेत्रो पर पुराने ठेकेदारो के नक्शे कदम पर चलते हुये गांव-गांव अवैध पैकारियां चलाने वालो को उधार हाल और गांव तक शराब स्कूटी व अन्य गाडियों के माध्यम से बेचने की सुविधा दे दी है। हालांकि आबकारी विभाग और पुलिस को सब पता है कि किस किस गांव मे कौन कौन अवैध शराब बेचने के धंधे मे लगा है। बावजूद इसके उन पर नही बल्कि अन्य किसी के द्वारा अवैध बिक्री किये जाने पर कार्यवाही की जाती है दूसरी ओर थानावार लगभग प्रतिदिन आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम तो हो रहे हैं जिससे पुलिस के रिकार्ड मे कार्यवाही के आंकड़े तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता मे अवैध शराब बिक्री रोकने का मकसद पूरा नही हो पा रहा है। सतना शहर सहित आसपास के 80 फीसदी गांवों में शराब ठेकेदारो द्वारा अवैध रूप से बिना रोक-टोक शराब बेची जा रही है। शराब ठेकेदार ने बाकायदा अपने खास लोगों के घर तक शराब पहुंचाने के लिये स्कूटी व बोलेरो के माध्यमों से भिजवाता है। जब जिसकों ज़िह जगह पर शराब चाहिए, स्थानीय कुछ खास लोगों के द्वारा वहां तक पहुंचा दिया जाता है। गांवों की स्थिति यह है कि गांव वालों को पानी की तलाश में मीलों भटकना पड़ता है पर मदिरा प्रेमी को गांव में ही बिना मशक़त किये शराब उपलब्ध हो जाती है। अवैध रूप से एक लाइसेंस पर गांव-गांव में संचालित की जा रही शराब बेचने



वालो ने गांवों का माहौल पूरी तरह से दूषित कर दिया है वही बेरोकटोक शराब दुकान का शटर हमेशा खुला ही रहता है। वर्तमान शराब ठेकेदारो ने अपनी जड़ मजबूत करते हुये आबकारी विभाग को अपने चंगुल फांस लिया है जिससे उनके जाल मे नोट फंसने के बाद चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। इसका कारण है कि आबकारी विभाग के सुस्त व लुंज पुंज होने की वजह से अब नये ठेकेदार बराबर सेटिंग बिछाने मे कामयाब हो गये हैं। मिल रहा मोटा सुविधा शुल्क- गांवों में शराब के कारण दिनों दिन अपराधों में वृद्धि हो रही है, सतना मे शराब के नशे मे कई अपराध भी हो जाते है या असामाजिक कृत्य हो जाते है शराब ठेकेदार द्वारा आसानी से गांव गांव तक शराब उपलब्ध करारकर भोले-भाले ग्रामीण को शराब की लत में जकड़ते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां अवैध रूप से शराब नहीं बेची जा रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस इस कारोबार से अंजान हो, बल्कि सारी जानकारीयां होते हुए भी मोटे सुविधा शुल्क के एवज में

इस कारोबार को अनदेखा कर रही है। ठेकेदारों ने जमाई जड़ें- पुराने ठेकेदारो के नक्शे कदम पर चलते हुये गांव गांव अवैध पैकारियां चलाने वालो को शराब बेचने की हर सुविधा दी जाती है। हालांकि आबकारी व पुलिस को पता है कि किस गांव मे कौन अवैध शराब बिक्री मे लिप्त है बावजूद इसके उस पर नही बल्कि अन्य किसी के द्वारा अवैध बिक्री किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। दुकानो की ओर से गांव गांव अवैध पैकारियों की बाकायदे गुटिस व आबकारी के पास लिस्ट होती है। शराब ठेकेदार की पैकारियों के अलावा किसी और ने अवैध शराब बिक्री जैसे शुरु की गई तो उस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। बिना डर होता अवैध परिवहन- दारू कम्पनी कई ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव तक शराब पहुंचाने के लिए पुलिस की सांठ-गांठ से जीपों से दिनदहाड़े परिवहन कराया जा रहा है। वहीं नगर के अवैध पैकारी करने वाले लोगों द्वारा बाईक से घर पहुंच सेवा प्रदाय की जा रही

है। फसाद की जड़ बन रही शराब- पुलिस की मिलीभगत से गांवों में चल रही अवैध शराब की बिक्री से कस्बों एवं छोटे-छोटे गांवों का माहौल दूषित हो रहा है। अवैध रूप से बेची जा रही शराब फसाद, लड़ाई, झगड़ों की जड़ बन चुकी है वही अवैध पैकारियों के चलते नशे का कारोबार बढ़ रहा है। युवाओ सहित बड़े बुजुर्ग तक नशे की लत मे पड़कर घरों मे कलहपूर्ण स्थिति निर्मित कर रहे हैं। दिखावे के लिए अभियान- विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा जब भी अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जाता है तो स्थानीय पुलिस व आबकारी विभाग के बीट प्रभारी द्वारा खाना पूर्त के लिए फर्जी तरीके से छोटे-मोटे प्रकरण बना दिए जाते हैं। शराब माफियाओं तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। आधी रात को भी मिलती है शराब- दुकानदार टाइम के बाद अलग कमरों में शराब बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, बेबाकी से बोल भी रहे हैं कि गोरखधंधे की मोटी कमाई का हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। कई ढाबों और होटलों में आधी रात को आसानी से शराब मिल रही है। बिक्री का समय तय होने के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश भर में शराब नीति लागू करने वाले मुख्यालय पर ही ये हाल है। सरकार को राजस्व हानि हो रही है तो शराब माफिया को भी शह मिल रही है। शराब पिलाने होटलों में बनाए स्पेशल कमरे, देर रात परोसी जाती है। देर रात शराब के शौकीनों को भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं होगी।

विकसित भारत के सपने को साकार करेगी भाजपा:- वीरेन्द्र कुमार

सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया सम्बोधित

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, भारतीय जनता पार्टी की चल रही सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को पार्टी के वरिष्ठ नेता 8 वार से सांसद केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार खटीक ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। हमारी पार्टी सर्वव्यापी, सर्व स्पर्षी सदस्यता अभियान चला रही है जिसमे समाज के सभी तबको को जोड़ा जा रहा हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ संगठन पर्व को मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि सतना जिले के कार्यकर्ता निष्चित तौर पर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। श्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि आगामी 26 सितम्बर तक सदस्यता संबंधित 60 प्रतिषत कार्य हमे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की दस जिलो मे सदस्यता अभियान की समीक्षा का कार्य पार्टी संगठन की ओर से सौंपा गया है, जिसे लगातार मै कर रहा हूँ। जिले के प्रवास पर आये केन्द्रीय मंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि हमारे पूर्व कार्यकर्ताओ ने अपने त्याग और तपस्या के आधार पर इस संगठन को खड़ा किया है। दो सांसदो वाली पार्टी आज विष्ण की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है इसमे कार्यकर्ताओ के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी



कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर समाज के सभी तबको को सदस्य बनाए उन्होंने आब्हान करते हुए कहा कि युवाओ को और महिलाओ को पार्टी से जोड़ने का व्यापक अभियान सदस्यता के इस अभियान मे चलाए। जिले के सभी बूथो मे चलाए सदस्यता अभियान- रणवीर सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं रीवा संभाग के संगठनात्मक प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता सदस्यता महा अभियान मे जुटे हुए हैं। जिले का कोई भी बूथ छूटने न पाए। दूर दराज और जिले के सभी आंचलो मे पहुंचकर लोगो को सदस्य बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, पापंद, जनपद सदस्य, जिला पंचायतो के सदस्य, विधायक, महापौर, सांसद

सभी सदस्यता अभियान मे जुटे हुए है। सतना जिले का संगठनात्मक संरचना बेहद मजबूत है, पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को गति देने मे लगे है। हमे और ताकत के साथ इस अभियान को गति देना है ताकि लाभार्थी वर्ग समेत ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बने। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल सिंह पटेल ने भी बैठक को सम्बोधित किया। संचालन जिला महामंत्री ऋद्धभ सिंह ने किया, आभार प्रदर्शन श्रीमती सरोज गुर्जर ने किया, मंच मे विधायक सुरेन्द्र सिंह गहरवार, महापौर योगेश ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, सदस्यता अभियान के जिला संयोजक धर्मेन्द्र सिंह बिसेन मंचासीन रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक ऊषा चौधरी,

अशोक गुप्ता, किरण सेन, मुरारी सोनी, सुधा सिंह, रमाकान्त गौतम, दीपनारायण सिंह, कामता पाण्डेय, जान्हवी त्रिपाठी, शुभम तिवारी, रेनु सिंह, श्रीकृष्ण द्विवेदी, जयप्रताप गुप्ता, श्याम लाल गुप्ता श्याम कृष्णा पाण्डेय, सौभाग्य केशरी, सीमा सिंह यादव, रामपाल यादव, प्रियंक त्रिपाठी, अभिषेकदत्त पाण्डेय, संजय अग्रवाल, रामसहाय गौतम, अरुण सिंह परिहार, शांतिस्वरूप अग्रवाल, शिवभगत मिश्रा, मनीष प्रताप सिंह, कार्तिकेय द्विवेदी, रामबेटा पाण्डेय, सुनील मिश्रा, बालकृष्ण शुक्ला, राजेश सिंह गहरवार, दीपेन्द्रनाथ त्रिपाठी, संतोष कुषवाहा, शिवम अग्निहोत्री, आनंद जायसवाल, अभिषेक तिवारी अंशू, ममता सोनी, रत्ना चतुर्वेदी, सुनीता कुषवाहा, आयुषी तिवारी, विनोद जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

निजी शालाओं के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, शिक्षा सत्र 2024-25 के लबित नामांकन एवं मेपिंग कार्य की शत प्रतिशत पूर्णता तथा गत वर्ष से वर्तमान सत्र में मेपिंग के अंतर का विश्लेषण, इस्पायर अवाई आइडिया अपलोड, निजी शालाओं में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारियों के दृष्टिगत शुक्रवार को सोमवारिया बाजार स्थित जनशिक्षा केंद्र एमएलबी और क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले निजी शालाओं के संस्था प्रधानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला परियोजना समन्वयक अरएस शिप्पे की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में निजी शिक्षण शालाओं के संस्था प्रधानों से प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा कर कार्य की प्रगति प्राप्त कर उनकी कठिनाईयों का निदान किया गया। बैठक में 80 से अधिक संस्था प्रधानों के साथ जनशिक्षक लोकेश राठौर, शिवनारायण कराड़ा, गोपाल कुभकार उपस्थित रहे।



वैज्ञानिकों ने ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का बताया तरीका

कृषि यंत्रों के चुनाव एवं रख-रखाव विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषक प्रशिक्षण संपन्न

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, कृषि विज्ञान केन्द्र शाजापुर द्वारा कृषि यंत्रों के चुनाव एवं रख-रखाव विषय पर कृषकों हेतु प्रशिक्षण ग्राम डंगीचा में 09 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसका समापन कृषि विज्ञान केन्द्र शाजापुर में 13 सितम्बर शुक्रवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष टैगोर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संतोष टैगोर ने बताया कि खेती को लाभप्रद बनाने हेतु कृषक उन्नत कृषि तकनीक एवं उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग कृषि विज्ञान के सलाह अनुसार करें, जिससे आर्थिक लागत कम होगी। प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ जीआर अंबावतिया के द्वारा कृषकों से अनुरोध किया गया कि पूरे प्रशिक्षण के दौरान उन्नत कृषि यंत्रों के संबंध में बताई गई तकनीकों का प्रयोग अपनी खेती-बाड़ी में करें। साथ ही खेती में अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यानिकी एवं औषधीय फसलों की खेती वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार करें। प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र के कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉ एसएस धाकड़ ने खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाने वाले उन्नत कृषि यंत्रों के चुनाव, रख-रखाव एवं उन्नत कृषि यंत्रों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विभिन्न फसलों की बुवाई हेतु हस्तचलित कृषि यंत्र डिबलर, पशु चलित बुवाई यंत्र के साथ रेज्ड बेड प्लांटर की विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि रेज्ड बेड प्लांटर से बुवाई करने पर



कम वर्षा की स्थिति में नमी का संरक्षण होता है एवं अधिक वर्षा की स्थिति में सुरक्षित जल निकास होता है। साथ ही ट्रैक्टर से चलने वाले विभिन्न जुताई, बुवाई, कटाई एवं गहाई हेतु उन्नत कृषि यंत्रों का उचित प्रचालन के साथ-साथ कृषि यंत्रों को चलाने से पहले, चलाने के दौरान एवं चलाने के बाद कौन-कौन सी सांत्वानी रखी जानी है इसके बारे में प्रशिक्षण के दौरान विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ गायत्री वर्मा, डॉ मुकेशसिंह, डॉ डीके तिवारी ने कृषकों को समसामयिक जानकारी दी। इस दौरान कृषकों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

ड्रोन से छिड़काव के बारे में

दी जानकारी- साथ ही फसलों में छिड़काव की उन्नत तकनीक ड्रोन का प्रदर्शन कृषि विज्ञान प्रक्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी प्रियंका सौष्टीय के सहयोग से किया गया। इस ड्रोन प्रदर्शन के दौरान केन्द्र के प्रमुख डॉ जीआर अम्बावतिया ने बताया कि आज के डिजिटल युग में खेती भी आधुनिक होती जा रही है, इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्र नये-नये कृषि यंत्रों का प्रदर्शन कृषि विज्ञान केन्द्र प्रक्षेत्र तथा कृषकों के खेतों पर कर रहा है, जिससे ड्रोन जैसी तकनीक से कम समय तथा कम लागत में कृषक ज्यादा उत्पादन ले सकें। यह तकनीक उद्यानिकी फसलों संतरा, अमरूद, आम के साथ-साथ गेहूँ, सरसों, अरहर, चना आदि फसलों के लिए काफी

उपयोगी है। ड्रोन तकनीक के प्रदर्शन के दौरान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ एसएस धाकड़ ने बताया कि ड्रोन स्प्रेयर एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसमें ड्रोन की आधुनिक तकनीक द्वारा फसलों में कीटनाशकों तथा घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। इस ड्रोन तकनीक के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट में 10 लीटर पानी में एक एकड़ खेत में दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जबकि हस्त चलित स्प्रे पंप से एक एकड़ में छिड़काव करने में 8 से 10 घण्टे तथा 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि ड्रोन की बैटरी को चार्ज करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस ड्रोन तकनीक से समय, पानी तथा लेबर की काफी बचत होती है। ड्रोन द्वारा सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव किया जा सकता है। इस दौरान केन्द्र वैज्ञानिक डॉ डीके तिवारी, डॉ गायत्री वर्मा, रंजेश विश्वकर्मा, हितेन्द्र इंदौरिया, निकितानंद, गंगाराम, हाफिज खां सहित 50 से अधिक कृषक उपस्थित रहे।

भारतीय किसान संघ की चेतावनी सोयाबीन 4892 एम एस पी स्वीकार नहीं 6000 प्रति क्विंटल खरीदे सरकार

शाजापुर में कालापीपल के तत्वाधान में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन



भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, भारतीय किसान संघ जिला शाजापुर की तहसील कालापीपल के तत्वाधान में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन तहसील कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया जिसमें हजारों की संख्या मे सैंकड़ों ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे सड़कें हुई जाम भारतीय किसान संघ तहसील कालापिपल के तत्वावधान मे विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई कृषि उपज मंडी प्रांगण में एकत्रीकरण के साथ सभा का आयोजन किया गया जिसमें संभाग मंत्री घनश्याम पाटीदार संभागीय सदस्य राज बहादुर सिंह गुर्जर जिला मंत्री मुकेश पाटीदार संभागीय सदस्य सोहन सिंह सिसोदिया जिला शाह मंत्री राधेश्याम जी मीणा द्वारा सभा को संबोधित किया गया जिसमें संभागीय सदस्य पाटीदार में सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर वर्तमान केन्द्र राज्य सरकार के माध्यम से किसानों की समस्याएं खासकर सोयाबीन के काम भाव जो विगत

10 साल पूर्व ?3500 क्विंटल बिक रहे थे वही भाव पर सोयाबीन आज बिक रही है उसे बढ़ाकर ?6000 प्रति क्विंटल एसपी तय कर मंडियों में खरीदने की व्यवस्था करें ताकि किसानों को अपनी फसल का लागत निकल सके जिला मंत्री पाटीदार द्वारा बताया गया कि सरकार वर्तमान में किसानों पर ध्यान न देते हुए उद्योगपतियों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है किसानों के नाम पर वोट लेने के बाद किसानों की शुद्ध लेना बंद कर दी गई है सरकार होश में आए और किसान को इस मांग के आधार पर?6000 प्रति क्विंटल एसपी तय करें और खरीदने की व्यवस्था की जावे अन्यथा भारती किसान संघ आने वाले समय में जिला केंद्र पर धरना प्रदर्शन कर सभी मंडिया में तालाबंदी करेगा उसके बाद भगवान बलराम जी की शोभायात्रा के साथ हजारों किसान 400 ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के साथ नगर के मुख्य मार्गों से जय घोष लगाते हुए तहसील केदो पर धरने के रूप में बैठे किसानों ने



सरकार को ललकारा और अपनी मांग रखी जगह जगह नगर वासियों ने पूजा अर्चना की नगर यातायात व्यवस्था सुचारू करने में पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला रैली के साथ यात्रा तहसील कार्यालय पहुंचेगी जहा किसानों ने सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी की वर्तमान सरकार ने जो किसान को सोयाबीन के फसल के भाव बंद कमरों में बैठकर 4892 तय करें हैं वह भारतीय किसान संघ और जिले के किसानों को मान्य नहीं है सोयाबीन का भाव 6000 प्रति क्विंटल सरकार एसपी तय कर खरीद की व्यवस्था की जावे तहसील के किसानों के खेतों को नर्मदा का पानी मिले ऐसी अनेक मांगों के साथ मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय के नाम कैलाश सस्तिया के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन के समय कृषि से संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही जिन्हें किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया कार्यक्रम जिसमें केंद्र राज्य को प्रमुख मांग जिले में जंगली

जानवरों के द्वारा नुकसान फसलों में हो रहा है इसे अनदेखा न करें उसके लिए वन विभाग व राजस्व विभाग मिलकर किसानों को प्रति हेक्टेयर?80000 रुपय राहत राशि दिलवाई जावे अभी अनेक मांगों को लेकर तहसील केंद्र पर ज्ञापन दिया गया जिसमें उपस्थित कार्य करता तहसील अध्यक्ष दिलीप जी मेवाड़ा तहसील मंत्री प्रहलाद सिंह राजपूत तहसील उपाध्यक्ष राधेश्याम सोलंकी तहसील उपाध्यक्ष अशोक पाटीदार उपाध्यक्ष अशोक अमृत्य तहसील सदस्य अचल सिंह मेवाड़ा सदस्य आदेश सक्सेना राय सिंह मीणा महेश मीना राधेश्याम चंद्रवंशी ओम प्रकाश पाटीदार इंद्र सिंह नागेंद्र सिंह दिनेश अरविंद मेवाड़ा रामेश्वर धनगर ओम प्रकाश पाटीदार जीतमल पाटीदार हरिनारायण मेवाड़ा दिनेश जयराम सिंह सिसोदिया नागेंद्र सिसोदिया दिनेश प्रहलाद सिंह मीणा दागोटिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे जानकारी धर्मेन्द्र पाटीदार तहसील मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई

मैहर उपचुनाव में विरोधियों को दिया जवाब

तमाम चक्रव्यूहों को भेदते हुए मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने वार्ड क्रमांक 2 पर दर्ज करवाई जीत



श्री निवास मिश्रा । सिटी चीफ मैहर, मैहर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में हुए पार्षदी उपचुनाव पर चुनाव भले ही पार्षदी का था पर शाख पूरी मैहर विधायक की लगी थी क्योंकि मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं उनका काम करने का अपना एक अलग तरीका है इसी बात से विरोधियों के साथ-साथ कुछ अपनों ने भी इस चुनाव में अपना असली रंग दिखाया और विधायक को सबक सीखने की सीढ़ी पर एक लगन सील नेता और जिस पर जनता का आशीर्वाद हो उसे किसी के नाराज और साथ ना रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य मैहर का विकास एवं भारतीय जनता पार्टी की मंशानुसार गरीबों और वंचितों का मुख्य धारा से जोड़ना एवम शासन सरकार की सभी योजनाओं का उनका लाभ दिलवाना एवम हर परिस्थितियों सुख-दुख में जनता के साथ खड़े रहना एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, वही विधायक ने वार्ड क्रमांक 2 के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सभी जनता जनार्दन के लिए मैं 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा आपकी सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है.

जिले में आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत उन्मुखीकरण सहप्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

कार्यक्रम में वाटरशेड के डीपीओ विश्वास तारे, केवीके के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ जीआर अंबावतिया, पशुपालन विभाग से परियोजना सहायक संचालक डॉ प्रशान्त समेत अन्य उपस्थित थे

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 प्रबंधन मिशन के सहयोग से आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं सीपा संस्था द्वारा जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर की अध्यक्षता में जिला उन्मुखीकरण सहप्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाटरशेड और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के संयुक्त प्रयास से जिले में होने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को कार्यक्रम में वरिष्ठ जिला समन्वयक शैलेन्द्रसिंह जादीन द्वारा पीपीटी के माध्यम से अपने चार स्तंभों जलवायु कुशल, कृषि प्राकृतिक संसाधन,



आजीविका विविधीकरण और कृषकों संस्थागत जुड़ाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान आगामी दिनों में होने वाले परियोजना कार्यों को भी समझाया। कार्यक्रम में वाटरशेड के डीपीओ विश्वास तारे, केवीके के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ जीआर अंबावतिया, पशुपालन विभाग से परियोजना सहायक संचालक डॉ प्रशान्त, एनआरएलएम मनरेगा

ब्लॉक कोरडीनेटर नितेश यादव, कृषि विभाग सहायक संचालक अरविन्द राजपूत, उद्यान विभाग उपसंचालक मनीष चौहान सहित वाटरशेड के ब्लॉक लेवल के अधिकारी एवं सीपा संस्था के राज्य स्तरीय परियोजना समन्वयक पंकज चौधरी, जिला समन्वयक रोहित चौहान, कम्प्युनिटी मोबिलाइजर सुनील परमार उपस्थित थे।

त्योहारों को देखते हुए नगर में शांति व्यवस्था बनाए रहने हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया फेलेग मार्च

कलेक्टर रानी बाटड़ एवं पुलिस अधिक्षक सुधीर अग्रवाल की उपस्थिति में निकली गयी फेलेग मार्च

श्री निवास मिश्रा । सिटी चीफ मैहर, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में फेलेग मार्च किया गया। विगत वर्षों की भांति दिनांक 07.09.2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक परम्परागत गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, ईद मिलाद-उन-नबी, विश्वकर्मा जयंती, अनन्त चतुर्दशी, पर्युषण पर्व (जैन समाज) गांधी जयंती, पितृमोक्ष अमावस्या, महानवमी दशहरा, दीपावली पर्व मनाने के लिये की जाने वाली व्यवस्थायें व्यवस्थित रखने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये मैहर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा त्योहारों को देखते हुए। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रहने हेतु शुक्रवार को कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़ एवं पुलिस



अधिक्षक श्री सुधीर अग्रवाल जी की उपस्थिति में नगर भर में फेलेग मार्च निकाला गया जो की मैहर थाना से प्रारंभ हो कर पुरानी बस्ती, रंगलाल चौराहा, अग्रसेन चौक, अलाउद्दीन तिराहा, घंटाघर, कटराबाजार,काली माता मंदिर, रेलवे स्टेशन, स्टेट बैंक चौराहा,

चंडी माता मंदिर, होते हुए घंटाघर में समापन किया गया इस मौके पर एसडीएम श्री विकास सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक श्री मुकेश वैश्य, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी सहित पुलिस बल उपस्थित रहे।

मुखबिर की सूचना फुनगा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही 41.60 लाख का मशरूका जप्त

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, पुलिस चौकी फुनगा द्वारा (03 पिक अप वाहन में क़रूरता से लदे मवेशी पड़वा/भैंस 18 नग कीमती 3 लाख 60 हजार एवं तीनों पिक-अप वाहन सहित 41.60 लाख का मशरूका जप्त कर की गई कार्यवाही। आज दिनांक 13.09.24 को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक रूक्मा887454, पिकअप वाहन क्रमांक रूक्मा887454, पिकअप वाहन सोल्ड मे कम जगह में टूस- टूस कर भैंस पडा लपटा के जंगल से लोड कर ब्यूहारी ले जाए जा रहे हैं, की सूचना पर हमराह स्टाफ आर 345 आदेश सक्सेना राय सिंह मीणा महेश मीना राधेश्याम चंद्रवंशी ओम प्रकाश पाटीदार इंद्र सिंह नागेंद्र सिंह दिनेश अरविंद मेवाड़ा रामेश्वर धनगर ओम प्रकाश पाटीदार जीतमल पाटीदार हरिनारायण मेवाड़ा दिनेश जयराम सिंह सिसोदिया नागेंद्र सिसोदिया दिनेश प्रहलाद सिंह मीणा दागोटिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे जानकारी धर्मेन्द्र पाटीदार तहसील मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई



जयसिंहनगर , अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार जिला शहडोल (म0प्र0) का होना बताए तथा उक्त मवेशियों को आरोपी मोहित सिंह निवासी बुढ़ार , आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यूहारी के कहने पर परिवहन करना एवं मवेशियो को व्यापारी अर्जुन राठौर निवासी ग्राम लपटा ने लोड कराया था । पिकअप वाहन रूक्मा8871345, रूक्मा887454 व सोल्ड में लोड मवेशियो के सीगो, पैरों को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बाँधी मे क़रूरता पूर्वक बांधकर टूस टूस कर लादा गया था । मामले में वाहन मालिकों पीरुहीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण में कुल 07 आरोपी 1. मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार , सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना

उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर , 3. अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार जिला शहडोल (म0प्र0) 4. आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यूहारी 5. मोहित सिंह निवासी बुढ़ार 6. पीरुहीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, 7. शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध पशु क़रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6(क),9,10,11 एवं रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन माल वाहक मे मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192 एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 333/2024, 334/2024, 335/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना मे ले लिया गया है शेष बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। उक्त कार्यवाही में- चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक श्रीमान सुमित कौशिक, प्र.आर. 88 उमेश केवट, आर 345 राकेश कनासे , 348 वीरसिंह पाल शामिल रहे।

भाजपा सदस्यता अभियान के निमित्त देवबंद नगर मंडल में बूथ संख्या 247 पर हुई बैठक में सदस्यता अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारीयां दी गई

प्रदीप सैनी ने कार्यकर्ताओं को भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के प्रति जानकारी दी और उन्हें सदस्यता भी दिलाई

गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद (सहारनपुर), भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के निमित्त देवबंद नगर मंडल में बूथ संख्या 247 पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यता अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारीयां दी गई। पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सैनी, डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जिला अध्यक्ष, देवबंद नगर उपाध्यक्ष विकास त्यागी, मंडल संयोजक विशाल गर्ग और बूथ अध्यक्ष उमंग शर्मा, प्रदीप चोपड़ा, प्रमोद शर्मा, राजेश अनेजा, विश्वाकांत शर्मा, नितिन मि्तल, आदेश अग्रवाल, हरविंदर बेदी, अमित तायल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदीप सैनी ने कार्यकर्ताओं को भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के प्रति जानकारी दी और उन्हें सदस्यता भी दिलाई।



भाजपा का कार्यकर्ता होना बड़ा गर्व - वीरेंद्र खटीक

भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर मैहर में भी बैठक

श्री निवास मिश्रा । सिटी चीफ **मैहर**, मैहर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी द्वारा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता महा अभियान को जोर शोर से शुरू किया गया है इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सभी केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सदस्यता सर्वप्रथम दिलाई गई उसके पश्चात पूरे भारत देश के अंदर मतदान केंद्र तक के सदस्यता अभियान का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है इसी कड़ी में आज सदस्यता अभियान को लेकर मैहर में बैठक आयोजित की गई जिसमें बैठक में मुख्य रूप से भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक एवं प्रदेश के महामंत्री एवं रीवा संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह रावत मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने की उपस्थिति में आयोजित की गई इस बैठक में मुख्य रूप से सर्वप्रथम मां भारती की प्रतिमा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं अतिथियों का स्वागत मोनिका दहिया जिला महामंत्री द्वारा किया गया इसके अतिरिक्त सदस्यता अभियान की बैठक को लेकर के मुख्य बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने द्वारा उपस्थित अतिथि और कार्यकर्ताओं के सामने ब्यावर रखा गया इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक द्वारा कहा गया कि भाजपा उस शिखर को पाने जा रही है इसके आसपास तक आज तक किसी दल ने उपलब्धि नहीं हासिल की है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान हमारे देश



की एक बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका दिख रहा है वही देखा जा रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रेरित होकर उसकी कार्य कुशलता की क्षमता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आगे आ रहे हैं पहली बार देखा जा रहा है कि इस महा अभियान सदस्यता में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं । सदस्यता अभियान कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा की घड़ी रणवीर सिंह रावत संभागीय प्रभारी रणवीर रावत जी ने सदस्यता अभियान को लेकर के मंडल के कार्य योजना बैठक में समीक्षा की जिसमें उन्होंने सभी मंडल एवं प्रभारी से एका एक चर्चा की और उन्होंने इस सदस्यता अभियान को लेकर के मूल मंत्र दिया रणवीर सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश भर में 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दया है जिसमें मैहर जिले को को 2 लाख सदस्य बने हैं लक्ष्य मिला हैं जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी शक्ति के साथ मतदान केंद्रो पर उतरना पड़ेगा और इस लक्ष्य को पाने के बाद मैहर जिला भी पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 सूची में अपना नाम करें इसकी चिंता जिले के पदाधिकारी को करनी चाहिए यह कार्यकर्ताओं की परीक्षा की खड़ी है जिसे बड़ी आसानी से पास किया जा सकता है कार्यकर्ताओं की एकजुट से मिली वार्ड नंबर 2 में चुनाव पर बड़ी जीत मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि जिस शक्ति के साथ उपचुनाव वार्ड नंबर 2 में पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की है उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हमें सदस्यता अभियान को भी

तेजी से बढ़ाकर लोगों तक सदस्यता अभियान की जोत को तेजी से जलानी है और दिए गए लक्ष्य को समय पर पूरा करने में सब को अपनी सेभागिता दिखाना पड़ेगा ! संगठन की पूंजी है कार्यकर्ता- कमलेश सुहाने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने ने कहा कि संगठन की पूंजी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के कर्मठ काम को लेकर के आज विश्व में एक शक्ति का प्रतीक बनी है जिस पर उन्होंने सभी मंडल एवं बृथ प्रभारी एवं शक्ति केदो के प्रभारी को सदस्यता अभियान में तेजी से लाने के लिए अपील की है कार्यक्रम का आभार महामंत्री गोरैलाल द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का सफल संचालन महामंत्री विश्वनाथ तिवारी द्वारा किया गया इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ता एवं बृथ प्रभारी काफी मात्रा में उपस्थित रहे जिसमें मुख्य रूप से नितिन ताम्रकार डॉक्टर रविशंकर द्विवेदी कुलदीप तिवारी जयंती महेश तिवारी चंदा सिंह रेखा दुबे सावन जायसवाल जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह मंजूसर से मीडिया प्रभारी प्रमोद सिंह गुड्डा चौरसिया सूर्य प्रकाश चौरसिया पवन दुबे जितेंद्र शुक्ला इंद्रपाल पटेल आरती अग्रवाल सूरज गुप्ता धीरेंद्र द्विवेदी भक्तन राहुल शर्मा दुर्गेश पांडे दिनेश मौर्य प्रसन्न सिंह राजा पांडे जितेंद्र पटेल अमरपाटन आदित्य नारायण शुक्ला सुजीत शिवहरे आशीष शिवहरे समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

धनंगवा में पीएमजीकेवाय के कमीशन खेला खेल, जांच में होगा खुलासा

रिश्तेदारों की फर्जी भर्ती मामले में टीम गठित, होगी

कार्यवाही, तुलावटी सहकारिता के कर्मचारी नहीं

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनूपपुर, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित धनगवां में शासन से प्राप्त पीएमजीकेवाय खाद्यान्न में कमीशन का खेल एवं प्रबंधक द्वारा अपने रिश्तेदारों की फर्जी भर्ती के मामले की खबर पर सहकारिता उपायुक्त सुनीता गोटवाल ने सहकारिता निरीक्षक (प्रशासक) अनुज ओहदार को जांच के निर्देश दिए गए हैं, जहां प्रशासक अनुज ओहदार ने समिति धनगवां से उक्त संबंध में दस्तावेज एवं कॉंपरेटिव बैंक से स्टेटमेंट सहित अन्य दस्तावेज लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजना अंतर्गत सहकारी समिति धनगवां ईआरपी पोर्टल में इनबिल्ट हो चुकी है, जिसमें दर्ज पीएमजीकेवाय का कमीशन माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक का 2 लाख 61 हजार 369 का दर्ज भुगतान ऑनलाईन देखा जाएगा। अगर ईआरपी पोर्टल में उक्त भुगतान संबंधी किसी तरह के दस्तावेज नहीं होंगे तो निष्पक्ष रूप से जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

यह था मामला- सहकारी समिति धनगवां के प्रबंधक सालिक राठौर द्वारा कोरोना काल में आपदा के अवसर का लाभ उठाते हुए पीएमजीकेवाय खाद्यान्न के कमीशनी की राशि का खेल खेलते हुए लाभ उठाया गया। अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक के खाद्यान्न के कमीशन में प्रबंधक द्वारा अप्रैल 2021 में आवंटित किए गए निष्पक्ष विक्रेताओं के खाते में 31 जुलाई 2023 को उक्त राशि डालकर बंदर्बाट करते हुए समिति को नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि अप्रैल 2021 में कनिष्ठ विक्रेताओं को दुकान आवंटित की गई थी, तो फिर उन्हे अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 के खाद्यान्न का कमीशन कैसे दे दिया गया।

दो सहायक प्रबंधक की लड़ाई में मिला था प्रभार- वर्ष 2013-14 में समिति धनगवां के दो सहायक प्रबंधक हीरामणि द्विवेदी एवं नथू पटेल द्वारा



संस्था प्रबंधक के प्रभार के लिए आपसी खिंचातान चलती रही है, जिसको देखते हुए संचालक मंडल की सहमति से उपपंजीयक सहकारिता द्वारा विक्रेता सालिक राठौर को प्रबंधकीय कार्य हेतु अधिकृत किया गया था। जिसके से अभी तक समिति धनगवां के प्रभारी प्रबंधक के चार्ज में अब तक कार्य कर रहे हैं।

तुलावटी सहकारिता के कर्मचारी नहीं- पूरे मामले की जानकारी सहकारिता उपायुक्त अनूपपुर सुनीता गोटवाल से ली गई, तो उन्होने बताया कि तुलावटी सहकारिता विभाग के कर्मचारी नहीं होते हैं, उन्हे सेल्समैन द्वारा स्वयं अपने खर्च में रखा जाता है। इसके बाद प्रभारी प्रबंधक बनते ही सालिक राठौर द्वारा वर्ष 2017 एवं 2018 में अपने सगे रिश्तेदार दिनेश सिंह राठौर शासकीय दुकान महदुा एवं विजय सिंह राठौर को क्योटेार दुकान का संचालन दिए जाने के बाद बिक्री की रसीद और बिल में स्वयं प्रबंधक सालिक राठौर के हस्ताक्षर होते रहे हैं। इसके साथ ही उपायुक्त सहकारिता विभाग अनूपपुर ने धनगवां के प्रबंधक सालिक राठौर के सगे संबंधियों की भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 10 एवं 12 वीं के मार्कशीट की जांच के लिए कहा गया है।

कैशबुक में पूर्व के कर्मचारियों की भांति इनके नाम होना चाहिए दर्ज- सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के पूर्व

संस्था में तुलावटी या फिर कोई अन्य कर्मचारी के रूप में कार्य किए होंगे तो संस्था के समस्त रिकार्डों में इनका नाम अंकित होना चाहिए। जैसे जमा रसीद, बिल बाउचर, वेतन बिल रजिस्टर्ड एवं उपस्थिति पंजीयक एवं इनको किए गए वेतन के कैश बुक में पूर्व वीणों की भांति अन्य कर्मचारियों की तरह इनका नाम दर्ज होना चाहिए, जिसकी भी जांच आवश्यक है। एवं संस्था के वित्तीय वर्ष समापन के पश्चात संस्था के बैलेंस शीट में सभी कर्मचारियों की सूची एवं प्राप्त वेतन की जानकारी दर्ज होती है, जिसकी भी जांच कराई जा रही है।

बिना भर्ती के 2018 में बना लिए थे फर्जी प्रस्ताव - जानकारी के जिसके बाद प्रभारी प्रबंधक बनते ही सालिक राठौर द्वारा वर्ष 2017 एवं 2019 में फर्जी भर्ती करा लिया गया, जबकि वर्ष 2019 में शासन द्वारा उचित मूल्य की दुकान के लिए विक्रेता की कोई भर्ती ही नहीं निकाली गई। वर्ष 2019 से बाउचर के माध्यम कैश बुक में मजदूरी के नाम पर भुगतान किया गया, इसके साथ ही वर्ष 2019 के बाद समिति धनगवां के कर्मचारी बनाकर जिला सहकारी बैंक शाखा जैतहरी में बचत खाता खुलवाते हुए विक्रेता बनाकर भुगतान किया गया है। जबकि सालिक राठौर वर्ष 2012-13 में शासकीय दुकान क्योटेार एवं कल्याणपुर का विक्रेता था एवं वर्ष 2014 में समिति धनगवां के प्रभारी

प्रबंधक बने थे।

धनगवां के प्रबंधक की बड़ी मुश्किले, करतूतों का होगा खुलासा- समिति धनगवां के प्रबंधक सालिक राठौर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया, जहां पीएमजीकेवाय के कमीशन में किए भ्रष्टाचार और काले करतूतों को छिपाने के लिए खबर लाने के दो दिनों बाद धनगवां में पुराने सेवानिवृत्त हो चुके सेल्समैन के यहां बैठक कर पुराने विक्रेताओं जिनमें पुणेन्द्र सोनी, अजय पाल पटेल, महेन्द्र कुमार गुप्ता सहित सगे संबंधी विक्रेता विजय सिंह एवं दिनेश सिंह राठौर को बुलाकर पुराने डेट 10 अगस्त 2023 में फर्जी भुगतान वाउचर बनाकर एवं कैश बुल में फर्जी इंट्री किया गया है, जहां नए कनष्ठि विक्रेताओं से वसूली बताकर पुराने विक्रेताओं को भुगतान दिखाया गया है। इस खेल में पुराने छुटे हुए (कटनी बुक) रसीद बुक का उपयोग लाया गया है, जिसका खुलासा उसी अवधि की कैश बुक की जांच कर सच्चाई सामने आ जाएगी। इतना ही नहीं उक्त कैश बुक की इंट्री एवं प्राप्त राशि एवं भुगतान बाउचर ईआरपी पोर्टल पर देखी जा सकती है कि उक्त बाउचर इंट्री है या नहीं।

इनका कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है, बैंक सहित ईआरपी पोर्टल में भी उक्त भुगतान के संबंध की जांच की जा रही है।

अनुज ओहदार, सहकारिता निरीक्षक (प्रशासक) अनूपपुर इनका कहना है तुलावटी सहकारिता विभाग के कर्मचारी नहीं होते है ना ही इनका भुगतान विभाग से किया जाता है। इसके लिए सेल्समैन स्वयं अपने खर्च पर मजदूर के रूप में तुलावटी को रखते है।

सुनीता गोटवाल, उपायुक्त सहकारिता विभाग अनूपपुर

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई

जिला पर्यावरण समिति की बैठक

वेस्ट प्लास्टिक एकत्रित करने के लिए चलाया जायेगा अभियान, श्रमदान कराते हुए कराया जाए वेस्ट प्लास्टिक एकत्रित :- डीएम मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण और गंगा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में हुए पौधरोपण की समीक्षा करते हुए जियो टैगिंग एक सप्ताह में करने के निर्देश उन सभी विभागो को दिए जिन्होंने अभी तक शेत-प्रतिशत टैगिंग नहीं की। मेला गुधाल में गठित कमेटी को निर्देशित किया कि पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खुले मैदानों में पड़े वेस्ट प्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स की टीम बनाकर श्रमदान कराते हुए प्लास्टिक को एकत्रित करने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने एकत्रित प्लास्टिक की शवयात्रा



निकालने के भी निर्देश दिए। इकठ्ठा प्लास्टिक का निस्तारण करने के लिए नगर निगम को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कैलाशपुर वेटलैण्ड में गिर रहें गंदे पानी के निस्तारण के संबंध में नाले की सफाई के साथ उस क्षेत्र को विकसित करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। डीएम मनीष बंसल ने बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के संबंध में जानकारी लेते हुए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए कि जनपद के सभी रजिस्टर्ड अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट की जानकारी उपलब्ध कराएं।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे मेड़ता रोड

नहीं उतरे कार से, दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता हुए निराश



ही मेड़ता रोड और की धरती पर कदम रखा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मेड़ता रोड के भाजपा कार्यकर्ताओं से तरीके से बात तक नहीं की तब मेड़ता रोड के भाजपा कार्यकर्ताओं को भारी निराशा हाथ लगी। विधानसभा अध्यक्ष का मेड़ता रोड नहीं रुकना कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं निर्धारित किया गया था। जिसकी खबर सुनकर भाजपा कार्यकर्ता कस्बे के नागौर रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए तथा वहां पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष नागौर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उनका दौरा नागौर जिले के मेड़ता सिटी उपखंड के गांव जैसास में एक शोक सभा से लेकर गोटन के सबसे बड़े प्लांट जेके में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना था इस दौरान उनका रूट वाया मेड़ता रोड होकर निर्धारित किया गया था। जिसकी खबर सुनकर भाजपा कार्यकर्ता कस्बे के नागौर रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय में उपस्थित हुए तथा वहां पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष नागौर जिले के दौरे पर थे।

पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का मेड़ता रोड में हुआ स्वागत

जोधपुर जाते समय रुके मेड़ता रोड, पदाधिकारियों

और कार्यकर्ताओं से की बात

एजाज अहमद उस्मानी । सिटी चीफ **मेड़ता** रोड, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट जयपुर –जोधपुर इंटरसिटी से जोधपुर जाते समय मेड़ता रोड होते हुए निकले। जिनका मेड़ता रोड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत करते हुए मोमेंटो भेंट किया।क्षेत्रवासियों ने गुहाला, नीमकाथाना बाइपास, पाटन और हसामपुर में स्वागत किया गया। सचिन पायलट के मेड़ता रोड पहुंचने की खबर सुनकर कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे तथा वहां पहुंचकर प्लेटफार्म संख्या एक पर रुकने वाली जयपुर जोधपुर



इंटरसिटी एक्सप्रेस में मौजूद सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि मौका मिलेगा तो अवश्य एक बार मेड़ता रोड आऊंगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही देश में एक बार फिर कांग्रेस का बहुमत लेंगे इसके लिए हम सभी कांग्रेसियों को एक होकर आदि करना होगा। उन्होंने

कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चली है। कांग्रेस के शासनकाल में ही राजस्थान की जनता को बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ निशुल्क स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा तथा बिजली, पानी तथा आवागमन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिला है। उनके स्वागत के दौरान रामनिवास लटियाल, लुमनाथ सपेरा ,युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आमिर खान, रामेश्वर गहलोत, कैलाश चंद शर्मा, मुनीर अहमद कुरैशी, अब्दुल सत्तार, खुशींद अहमद, हाजी अब्दुल हनीफ, अहमद अली तथा संजु कासिम सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

विशेष प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए बिना हेलमेट के चलने

वालों पर करें कार्यवाही :- डीएम मनीष बंसल



गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जाम से मुक्ति, आवश्यकतानुसार साइनेज लगाने के साथ ही सड़क मार्गों पर दुर्घटनाओं को न्यून करने के लिए सड़क सुरक्षा के मानकों के तहत सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में विचार- विमर्श किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जाम की समस्या से मुक्ति के दृष्टिगत स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को 10 से 15 मिनट के अंतराल पर रखे जाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर उनका संवेदीकरण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि अगली

मानकों के तहत निर्धारित कार्यों को पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिये कि जनपद में दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर संकेतक लगाएं और ब्लैक स्पॉट को दूर करने के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही की जाए। हाईवे एवं सड़क किनारे स्थापित विद्यालयों के बाहर यातायात संबंधी संकेतक लगाने के निर्देश दिए। हाईवे पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर सघन कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा, एआरटीओ एम्पी सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि धर्मेन्द्र सिंह, शिक्षा, विद्युत, स्वास्थ्य, नगर निगम, पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।

भक्त संजय लटियाल,टाईगर कापड़ी, सीताराम, सुभाष,मुकेश बिश्नोई,पवन,आशु,शिवम,तेजाराम, आंकित,श्रवण,श्याम,प्रेम,किशोर,हेमंत, कैलाश,सचिन,अजय

मुँडेल,सुनील,कालू, महिपाल,विकास, किशन,पहलाद,अेनु, शांतिपाल नेता,हरसु,लोकेश,सुशील,सुनील,राहुन, देवीलाल,अशोक,नाथु,आदि गोभक्त मौजूद थे!



आ गई देश की पहली वंदे मेट्रो, न्यूनतम किराया 30 रुपए, जीएसटी अलग से

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर से ठीक एक दिन पहले अपने गृह राज्य गुजरात के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 16 सितंबर को देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वंदे मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और इसे चलाने के लिए पहला रूट भी तय हो गया है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया है। इस ट्रेन की सेवा भुज से अहमदाबाद के बीच मिलेगी। यह ट्रेन रास्ते में अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, समखियाली, हलवद, धांगध्रा, विरमगाम, चांदलोडिया और साबरमती में रुकेगी, जबकि वापसी में यह अहमदाबाद से रवाना होकर साबरमती, चांदलोडिया, वीरमगाम, धांगध्रा, हलवद, समखियाली, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार होते हुए भुज पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन हफ्ते में 6 दिन ही होगा। हर सप्ताह रविवार को भुज से इसकी सेवा नहीं मिलेगी जबकि अहमदाबाद से इसकी सेवा शनिवार को नहीं मिलेगी।

दैनिक यात्रियों की संख्या सर्वाधिक

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत मेट्रो का ये रूट इसलिए सबसे ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इस रूट पर दैनिक यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए, इन शहरों से इस ट्रेन को लांच किया जा रहा है। नई मेट्रो सर्विस के शुरू होने से भुज और अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले हजारों दैनिक यात्रियों को फायदा होगा। इसको इसी मकसद से डिजाइन किया गया है।आने वाले समय में इस देश के दूसरे शहरों के बीच भी शुरू किया जाएगा।



ट्रेन का ठहराव हर स्टेशन पर औसतन 2 मिनट

वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भुज से सुबह 05.05 बजे रवाना होकर अहमदाबाद सुबह 10:50 बजे पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन अहमदाबाद से शाम 05:30 बजे खुलेगी और रात में 11:10 बजे भुज पहुंचेगी। यह ट्रेन का ठहराव हर स्टेशन पर औसतन 2 मिनट का रहेगा। यह ट्रेन 5 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी। वंदे मेट्रो ट्रेन का किराया कम से कम 30 रुपये रखा गया है। इसके ऊपर यात्री को इस पर जीएसटी भी देय होगा। यदि कोई यात्री इस ट्रेन के जरिए 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 60 रुपये और जीएसटी समेत अन्य चार्ज देना होगा। मतलब कि एक किलोमीटर पर कम से कम 1.20 रुपये का किराया तो चुकाना भी होगा।

मंथली सीजनल टिकट भी वैलिड

वंदे मेट्रो ट्रेन में एमएसटी या मंथली सीजनल टिकट भी वैलिड होगा। लेकिन आम मेल और एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन के लिए जारी होने वाला एमएसटी इस ट्रेन नहीं चलेगा। इसके लिए अलग से एमएसटी जारी होगा जो कि वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली सीजन टिकट होगा। इसके लिए यात्रियों को क्रमशः सात दिन, 15 दिन और 20 दिन का सिंगल जर्नी का किराया चुकाना होगा।

100 से 150 किमी तक होगी स्पीड

भारतीय रेलवे ट्रेन को वैसे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन रूट में इसकी गति 100 से



150 किमी तक होगी। ये ट्रेन उन यात्रियों के लिए जो नजदीक के बड़े शहरों में नौकरियां करने लिए रोज आते जाते हैं। ट्रेन में लोगों के सफर को आरामदायक और सुकून भरा बनाने पर जोर दिया गया है। तभी तो इसे आधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है। इस ट्रेन को वंदे भारत के ही रोलिंग स्टॉक पर डेवलप किया गया है। इसलिए इसमें ऑटोमेटिक डोर लगाए गए हैं। ट्रेन के चलने के बाद कोई भी यात्री दरवाजे या पायदान पर खड़े नहीं हो सकेगा।

वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को फिलहाल 12 कोच के साथ चलाया जा रहा है। हर चार मेट्रो कोच का एक सेट डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके। रेलवे की योजना

बाद में वंदे भारत मेट्रो के कोच की संख्या को बढ़ाकर 16 करने की है।

15 सितंबर को एक साथ 10 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात

वहीं, पीएम मोदी 15 सितंबर को एक साथ 10 राज्यों के लिए दस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इन ट्रेनों की सौगात झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश को मिलने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रेनों की सौगात बिहार और ओडिशा को मिलने वाली है।

वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है।

वित्तमंत्री के सामने जीएसटी पर मजाक पड़ा भारी, मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली। जीएसटी कितना सही है और कितना गलत इसे लेकर आम लोगों के बीच हमेशा मतभेद रहता है। जीएसटी से सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापारी ही होते हैं तो जाहिर तौर पर उनके इस मुद्दे पर अपने कुछ विचार होंगे। अपने यही विचार व्यक्त करना एक रेस्टोरेंट मालिक को भारी पड़ गया। तमिलनाडु की जानी-मानी रेस्टोरेंट चेन श्री अन्नापूर्नी के मालिक श्रीनिवासन इस विवाद के केंद्र में हैं। कोयम्बटूर में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्रीनिवासन ने जीएसटी को लेकर मजाकिया अंदाज में कुछ बातें कहीं। उन्होंने बताया कि कैसे जीएसटी की वजह से व्यापारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि श्रीनिवासन तमिलनाडु होटल ओनर्स फेडरेशन के चेयरपर्सन भी हैं। श्रीनिवासन ने बैठक में कहा, मिठाइयों पर 5 परसेंट जीएसटी है लेकिन नमकीन जैसे स्नैक्स पर 12 परसेंट, क्रीम वाले बन पर 18 परसेंट जीएसटी है लेकिन बन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। कस्टमर कई बार कहते हैं- आप ऐसा करें कि मुझे सिर्फ बन दें दें उसमें क्रीम और जैम में खुद लगा लूंगा। श्रीनिवासन की बात सुनकर वहां बैठे व्यापारी हंस पड़े। खबरों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यह सुनकर हंसी।

मांगनी पड़ी माफी

इस मीटिंग की वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल हुई जो श्रीनिवासन और वित्तमंत्री के बीच हुई बैठक की थी। इस वीडियो को तमिलनाडु बीजेपी के किसी सदस्य की ओर से ही वायरल किया गया था। कुछ ही देर में यह वीडियो कई लोगों द्वारा



शेयर की जाने लगी और खूब आलोचना भी की गई। इस वीडियो में श्रीनिवासन को अपने बयान के लिए माफी मांगते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा कृपया उसके लिए मुझे माफ करें, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं। यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस और डीएमके ने बीजेपी की आलोचना की है।

राहुल गांधी ने जताई कड़ी नाराजगी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट करके इस तरह के बर्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे बिजनेस का मालिक लोक सेवकों से सरलीकृत जीएसटी की मांग करता है, तो उसकी गुजारिश को अहंकार और घोर अनादर समझा जाता है। मगर, जब कोई अरबपति मित्र

नियमों में बदलाव चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी उसके लिए लाल कालीन बिछा देते हैं।

अब तो छोटे व्यापारियों का अपमान भी किया जाने लगा

राहुल गांधी ने कहा कि छोटे व्यवसायों के मालिक पहले ही नोटबंदी, बेकार बैंकिंग सिस्टम, जबरन कर वसूली और विनाशकारी जीएसटी की मार झेल रहे हैं। अब तो उनका अपमान भी किया जाने लगा है। राहुल ने कहा, जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो वे अपमान करना शुरू कर देते हैं। एमएसएमई बरसों से राहत की मांग कर रहे हैं। अगर यह अहंकारी सरकार लोगों की बात सुनती तो समझ आता कि सिंगल टैक्स रेट के साथ सरलीकृत जीएसटी से लाखों व्यवसायों की समस्याएं हल हो जाएंगी।

काबुल। खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर, 2001 को आतंकी हमला कर अमेरिका को दहला दिया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत अमेरिका की दो सबसे ऊंची इमारतों पर हमला किया गया था, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। यह अमेरिका और दुनिया पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर मार गिराया था। उसके बेटे हमजा बिन लादेन के भी 2019 में मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वह जिंदा है और एक बार फिर से पूरी दुनिया में आतंकवाद की लहर पैदा करने के लिए ऐक्टिव हो गया है।

द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा जिंदा है और आतंकी संगठन अलकायदा के विस्तार की कोशिश में जुटा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमजा के साथ उसका भाई अब्दुल्ला बिन लादेन भी सक्रिय है। इस बारे में नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने रिपोर्ट तैयार की है, जो ऐंटी-तालिबान मिलिट्री संगठन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमजा अपने साथियों के साथ अफगानिस्तान में कैप कर रहा है।



रिपोर्ट में लादेन को बेटे को क्राउन प्रिंस ऑफ टेरर कहा जा रहा है। खबर है कि वह उत्तरी अफगानिस्तान के किसी ठिकाने में छिपा हुआ है और लगातार 450 स्नाइपर्स उसकी सुरक्षा में डटे हुए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही हालात बिगड़ गए हैं। अब तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। खबर है कि हमजा बिन लादेन पंजशीर के दारा अब्दुल्ला खेल जिले की ओर बढ़ गया है। वहां करीब 450 अरब और पाकिस्तानी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। यही नहीं उसके कमांड में अलकायदा को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलकायदा के आतंकी पश्चिमी

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

ऐंटी-रेप कानूनों की स्कूलों में कराई जाए पढ़ाई

कुवैत में मुसीबत में फंसी भारतीय की महिला, मंत्री से लगाई गुहार

नई दिल्ली। कुवैत में काम की तलाश में गई आंध्र प्रदेश की कविता का जीवन अचानक से एक बुरे सपने में बदल गया। आरोप है कि कुवैत में उसे एक कमरे में बंद कर रखा गया है और कई दिनों से न ही खाना दिया जा रहा है और न ही किसी से संपर्क करने की अनुमति। कविता का दर्द तब सामने आया जब उसने कुवैत से आंध्र प्रदेश के एक मंत्री को फोन कर कहा, मुझे बचाइए सर, ये लोग मुझे मार देंगे। कविता आंध्रप्रदेश के आन्नामाया जिले की

रहने वाली हैं। उसके घर में दो बच्चे और एक विकलांग पति है। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे काम के लिए कुवैत जाना पड़ा। मगर वहां पहुंचकर उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। कविता ने बताया कि जिस कंपनी में वो काम कर रही थीं वहां के मालिक ने उसे बंद कर दिया है, तब सामने आया जब उसने कुवैत से उसकी हालत बहुत खराब है। कविता ने वीडियो संदेश के जरिए आंध्र प्रदेश के मंत्री रामप्रसाद रेड्डी से मदद की गुजारिश की।

नई दिल्ली। रेप के खिलाफ बने देश और राज्यों के कानूनों के बारे में स्कूली बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इसे सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। ऐसी मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किए। जनहित याचिका में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्भया कानून है, पॉक्सो ऐक्ट

के तहत सख्त प्रावधान हैं। इसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ रेप समेत हिंसक वारदातों में कमी नहीं देखी जा रही। इसके अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सख्त कानून बनाते हुए सजा-ए-मौत तक का प्रावधान कर दिया है। इसके बाद भी घटनाओं में कमी नहीं देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि सख्त कानून अपनी जगह हैं, लेकिन वारदात करने वाले तत्वों को उनके

बारे में जानकारी ही नहीं है। इसलिए इनके बारे में स्कूली सिलेबस में ही पढ़ाया जाए और जब लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी तो वे शायद ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरें। सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा की ओर से दाखिल की अर्जी में कहा गया कि महज सख्त कानून बना लेना ही इसका समाधान नहीं है। आबाद पोंडा ने अर्जी में कहा कि समाज के सभी वर्गों तक यह जानकारी ही

नहीं पहुंच सकी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर क्या सजा हो सकती है। इसलिए सभी को सजग करने के लिए जरूरी है कि जानकारी को आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को किशोरावस्था से ही इनके बारे में पता हो। आबाद पोंडा ने कहा कि अकेले सख्त कानून बनाने से ही मसले का हल नहीं होगा बल्कि उसके मुख्य कारण को ही खत्म करना होगा। यह कारण है, समाज

की सोच। यदि समाज गलत तरीके से सोचता है तो फिर उसे ही बदलना होगा। यह बदलाव तभी होगा, जब स्कूली सिलेबस में ही जागरूकता फैलाई जाए। ऐंटी-रेप कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। यही नहीं याची ने कहा कि सख्त कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा। इससे तो यह संकट और बढ़ सकता है कि लोगों को गलत मामलों में फंसा दिया जाए।

20वीं समुद्री विकास परिषद की बैठक में राज्यों के 80 मुद्दों का समाधान

पणजी। गोवा में आयोजित 20वीं समुद्री विकास परिषद की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 80 से अधिक जरूरी मुद्दों का समाधान किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिवसीय कार्यक्रम में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित जरूरी मुद्दों का समाधान किया गया। वहीं आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 20वीं एमएसडीसी के दौरान कई राज्यों के 100 से अधिक मुद्दों पर विचार-विमर्श



किया गया और सफलतापूर्वक उनका समाधान किया गया।

मंत्री सबानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और गोवा के मंत्री एलेक्सो सेकेरा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इन चुनौतियों का भी बैठक में किया गया समाधान

इस बैठक में कई नई और उभरती चुनौतियों का भी समाधान किया गया, जिसमें संकट में फंसे जहाजों के लिए शरण स्थल (पीओआर) की स्थापना, सुरक्षा बढ़ाने के लिए बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी पहचान उपकरण (आरडीई) बुनियादी ढांचे का विकास और नाविकों को महत्वपूर्ण आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता देकर उनकी सुविधा प्रदान

करना, बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना और तट पर छुट्टी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक को किया संबोधित

जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए राज्य रैंकिंग ढांचे और बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

वहीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा कि एमएसडीसी भारतीय बंदरगाह विधेयक और सागरमाला कार्यक्रम जैसी

नीतियों और पहलों को संरक्षित करने में सहायक रहा है।

कई बंदरगाहों के विकास में मदद की

सबानंद सोनोवाल ने कहा, केंद्र सरकार, राज्यों और समुद्री बोर्डों के बीच प्रमुख मुद्दों को हल करके, परिषद ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के निर्बाध विकास को सुनिश्चित किया है, जिससे तटीय राज्यों को उभरते अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में एमएसडीसी के प्रयासों ने 50 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों के विकास में मदद की है, जो अब भारत के वार्षिक कार्यों का 50 प्रतिशत से अधिक संभालते हैं।